वर्ष : 34 | अंक : 287 | मुंबई, बुधवार, 24 दिसंबर 2025 | RNI: MAHHIN/49994/91 | मूल्य : 3 रुपए | epaper.dobajedopahar.com | संपादक : अरुण लाल | संरक्षक : एन. के. पुरोहित

DBD दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

बीएमसी चुनाव सीटों पर माथापच्ची

- पहले 52 फिर 90 का ऑफर
- 123 सीटों की मांग करने वाले शिंदे अब 112 पर अड़े

ठाकरे बंधुओं के गठबंधन पर सस्पेंस खत्म

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

बीएमसी चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।नामांकन प्रक्रिया 23 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए प्रदेश में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी दलों के गठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हो सका है। हालांकि ठाकरे बंधुओं के गठबंधन पर सस्पेंस खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन अन्य दलों के साथ गठबंधन की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है।

महायुति और विपक्षी दलों के गठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो सका फाइनल

महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे इंतजार के बाद शिवसेना (उद्धव) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा पल आ गया है। सांसद संजय राऊत ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर ऐलान किया कि बुधवार दोपहर 12 बजे उद्धव और राज ठाकरे का गठबंधन होने जा रहा है। राऊत ने दोनों नेताओं की एक साथ फोटो भी साझा की। सूत्रों के मुताबिक, गठबंधन मंगलवार को होना था, लेकिन कुछ सीटों को लेकर मतभेद के कारण इसमें देरी हुई। आखिरकार, सोमवार रात मुंबई और अन्य महानगरपालिकाओं में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई।

मातोश्री और शिवतीर्थ में लंबी बैठकों का दौर

सोमवार को पूरे दिन मातोश्री और शिवतीर्थ पर राजनीतिक बैठकों और बातचीत में बीता। संजय राऊत पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात के लिए उनके निवास पहुंचे। इसके बाद मनसे नेता बाला नांदगांवकर और नितिन सरदेसाई मातोश्री पहुंचे और उद्धव ठाकरे से चर्चा की। देर रात तक चल रहे सीट बंटवारे के विवाद के बाद दोनों दलों के नेताओं में सहमति बनी। खासतौर पर मराठी बहुल इलाकों शिवड़ी, दादर, माहिम, भांडुप और विक्रोली में सीटों पर खींचतान देखने को मिली, लेकिन राज ठाकरे ने अपने निर्देशों के बाद विवाद को सुलझा लिया।

सीट बंटवारा और संभावित शक्ति प्रदर्शन

सहमति के अनुसार, शिवड़ी में 3 सीटों में से 2 शिवसेना (उद्धव) और 1 मनसे के खाते में गई है, दादर में 2 सीटें साझा की गई हैं, माहिम में अधिकांश वार्ड विवादमुक्त हुए हैं। भांडुप और विक्रोली में अंतिम फैसले पर देर रात तक चर्चा हुई, जिसमें विक्रोली में मनसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खबर है कि गठबंधन की घोषणा के साथ ही ठाकरे बंधु मुंबई में जनसभा के रूप में शक्ति प्रदर्शन भी कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यह गठबंधन बीएमसी चुनाव और महाराष्ट्र की राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेने के बाद कांग्रेस वैकल्पिक गठबंधनों पर विचार कर रही है। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में शरद पवार से मुलाकात की, जिससे कांग्रेस–एनसीपी के पुराने गठबंधन के फिर से मजबूत होने के संकेत मिले हैं।

एमवीए के भीतर दरारें

ठाकरे भाइयों के गठबंधन ने महाविकास आघाड़ी (एमवीए) के भीतर नई दरारें पैदा कर दी हैं। मुंबई कांग्रेस ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव अकेले लड़ने का कड़ा फैसला लिया है और साफ कर दिया है कि वह राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस के इस एकतरफा फैसले से शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के प्रमुख शरद पवार नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को साथ लाने के लिए पर्दे के पीछे बातचीत जारी है, लेकिन मुंबई कांग्रेस इकाई अपने अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर अड़ी हुई है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में विपक्ष ने शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और एनसीपी (एसपी) के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी के रूप में चुनाव लड़ा था। लेकिन बीएमसी जैसे अहम चुनाव से पहले यह गठबंधन संकट में नजर आ रहा है। शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) एमवीए में एमएनएस को शामिल करने के पक्ष में हैं।

नहीं मान रहे शिंदे

मुंबई। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच सहमति अब तक नहीं बन पाई है। हालांकि, BJP ने शिवसेना के लिए नया सीट फॉर्मूला पेश किया है,जिसके तहत उसे अब 90 सीटों का ऑफर दिया गया है लेकिन यह प्रस्ताव भी शिवसेना को कम लग रहा है। सूत्रों के अनुसार उप मुख्यमंत्री शिंदे करीब दो दर्जन सीटों की और मांग कर रहे हैं।

एक और दौर की बातचीत

सूत्रों के अनुसार, गठबंधन की पहली बैठक में शिंदे गुट की शिवसेना ने 125 सीटों की मांग रखी थी, जबकि BJP ने तब केवल 52 सीटें देने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, सोमवार देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई अहम बैठक के बाद BJP ने सीटों की संख्या बढ़ाते हुए 90 कर दिया। बावजूद इसके शिंदे नहीं मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि पहले 123 सीटों की मांग करने वाले शिंदे ने अब अपनी मांग घटाकर 112 सीटें कर दी हैं। इसके बावजूद दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्द ही शिंदे के साथ एक और दौर की बातचीत करेंगे।

बीजेपी का रुख सख्त क्यों?

हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में शानदार प्रदर्शन के बाद BJP का रुख सख्त माना जा रहा है। पार्टी ने राज्यभर में 117 नगर पालिका अध्यक्ष पदों पर जीत दर्ज की है। इसके मुकाबले शिंदे गुट की शिवसेना को 53 और अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को 37 अध्यक्ष पद मिले हैं। इसी प्रदर्शन के आधार पर BJP अपने सहयोगियों को ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं दिख रही है।

अजित पवार पर सस्पेंस कायम

दूसरी तरफ, अजित पवार की NCP के BMC चुनावों में महायुति में शामिल होने को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है। अगर NCP मुंबई में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती है, तो मौजूदा सीट बंटवारे की पूरी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ेगा। NCP के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे ने कहा कि अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के मुंबई आने के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। महायुति के लिए सबसे बड़ी अड़चन NCP नेता नवाब मलिक को लेकर है। नवाब मलिक पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गंभीर आरोप हैं। BJP ने साफ शब्दों में कहा है कि वह नवाब मलिक को साथ लेकर चुनाव नहीं लड़ेगी।

मुंबई की बिगड़ती हवा पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुंबई की खराब एयर क्वालिटी पर सुनवाई करते हुए बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी और एमपीसीबी कमिश्नर को फटकार लगाई। कोर्ट अधिकारियों से गाइडलाइंस और लापरवाही को लेकर कई सवाल किए। दोनों अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हुए थे। एमिकस क्यूरी डेरियस खंबाटा ने अदालत को बताया कि कॉन्स्ट्रक्शन कार्यों से उड़ने वाली धूल प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण गाइडलाइंस को कानून के समान बताते हुए निर्देश दिया है कि सख्त निर्देश लागू किए जाएं। प्रशासन द्वारा जनवरी और जून की समय सीमा गुजर जाने के बाद भी कॉन्स्ट्रक्शन साइट्स पर सेंसर आधारित एयर मॉनिटर नहीं लगाए गए हैं। कोर्ट ने अधिकारियों की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल उठाए।

- बीएमसी और प्रदूषण बोर्ड से तत्काल कार्रवाई के निर्देश
- 1080 मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए

कागजों पर नियम, जमीन पर धूल?

एमिकस क्यूरी ने बताया कि गाइडलाइंस के तहत कॉन्स्ट्रक्शन साइट्स पर वाटर फॉगिंग, मलबे को ढकना, सीसीटीवी और सेंसर आधारित एयर मीटर जरूरी हैं। बीएमसी के पास इन नियमों का पालन कराने के लिए दस्ते हैं, लेकिन ग्राउंड पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि ये दिशा-निर्देश सिर्फ कागजी नहीं हैं, बल्कि कानून की ताकत रखते हैं। विकास के नाम पर लोगों की सेहत की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सैद्धांतिक रूप से योजनाएं बेहतरीन हैं, लेकिन जमीन पर अच्छी तरह से लागू न किया जाना बड़ी चूक है।

लापरवाही क्यों हुई?

हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है कि जनवरी में दी गई एक महीने की समय सीमा का पालन क्यों नहीं किया गया। जून भी गुजर गया और अब बीएमसी सेंसर के लिए आईआईटी कानपुर से सलाह ले रही है।

धीमी रफ्तार से क्यों काम कर रहा प्रशासन?

आंकड़ों के मुताबिक, सिर्फ एक-तिहाई कॉन्स्ट्रक्शन साइट ही एयर क्वालिटी का डेटा साझा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन बहुत धीमी रफ्तार से काम कर रहा है। बीएमसी ने बताया कि 1080 मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं, लेकिन उनमें से कई डेटा नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने इसे अधिकारियों की बड़ी लापरवाही माना।

कॉन्स्ट्रक्शन साइट्स पर मेटल शीट या ग्रीन तिरपाल क्यों नहीं नजर आता?

सुनवाई के दौरान जजों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट जाते वक्त 20-25 साइट्स में से शायद ही किसी पर 35 फीट ऊंची मेटल शीट या ग्रीन तिरपाल नजर आता है। कोर्ट ने कहा कि वे विकास रोकना नहीं चाहते, लेकिन बिल्डरों की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीएमसी कमिश्नर ने नवंबर में सरप्राइज चेक का दावा किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट में भारी उल्लंघन सामने आए हैं। बीएमसी ने अब आश्वासन दिया है कि वे आज फिर से साइट्स का निरीक्षण करेंगे।

लावारिस कुत्तों को कहीं भी खाना खिलाने से रोकना गलत नहीं

- बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर सोसायटियों में अक्सर होने वाले विवादों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम और स्पष्ट फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गैर-निर्धारित जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना देने से किसी को रोकना कानूनन अपराध नहीं है और इसे न तो गलत तरीके से रोकना माना जा सकता है और न ही अवैध। अदालत ने इस फैसले से आम नागरिकों और आवासीय समितियों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की पीठ ने पुणे के 42 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द कर दिया। एक महिला और उसके साथियों को अपनी हाउसिंग सोसायटी के गेट पर आवारा कुत्तों को खाना देने से रोका और कथित तौर पर उन्हें बाहर जाने से भी रोका।

गैर-निर्धारित जगह पर रोकना गलत नहीं

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फुटपाथ, सोसायटी के प्रवेश और निकास द्वार, स्कूल बस स्टॉप जैसे स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना देने से रोकना स्वैच्छिक बाधा या गलत तरीके से रोकना नहीं कहा जा सकता। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गैर-निर्धारित स्थान पर कुत्तों को खाना खिला रहा है और उसे रोका जाता है, तो यह कानून का उल्लंघन नहीं है।

बच्चों की सुरक्षा अहम

अदालत ने माना कि आरोपी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि सोसायटी में रहने वाले बच्चों और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। रिकॉर्ड में यह बात सामने आई कि उस सोसायटी में पहले भी कुत्तों के काटने और हमले की घटनाएं हो चुकी थीं। ऐसे में कुत्तों को उन जगहों पर खाना देने से रोकना, जहां बच्चों की आवाजाही रहती है, किसी भी तरह से अवैध नहीं कहा जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट और नियमों का हवाला

हाईकोर्ट ने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पुराने फैसलों और एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों का भी हवाला दिया। अदालत ने कहा कि इन नियमों में आवारा कुत्तों के लिए तय फीडिंग एरिया का प्रावधान है और उसी के अनुसार खाना दिया जाना चाहिए।

किडनी रैकेट मामले में फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार

डीबीडी संवाददाता | चंद्रपुर

महाराष्ट्र में किडनी रैकेट की जांच कर रही एसआईटी ने मामले में सोलापुर से एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर पर 10-12 लोगों को किडनी निकलवाने के लिए कंबोडिया के एक अस्पताल में ले जाने और कमीशन लेने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार फर्जी डॉक्टर की पहचान कृष्णा के रूप में हुई है, जो खुद भी कभी इस रैकेट का शिकार हुआ था, लेकिन बाद में किडनी रैकेट का एजेंट बन गया। वह पेशे से डॉक्टर से नहीं, बल्कि इंजीनियर है। मामले में अब तक पांच साहूकारों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक फरार है। मामले में एक किसान रोशन कुडे की शिकायत के बाद पुलिस जांच शुरू की थी।

अवसान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का 88 वर्ष की उम्र में निधन

जो उनके घर नहीं आए, उनसे मिलने उनके पास चले गए शुक्ल

एजेंसी | रायपुर

छत्तीसगढ़ में जन्में हिंदी साहित्य के मशहूर कवि, कथाकार और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया है। उनका छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एम्स में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने 88 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। विनोद कुमार शुक्ल जी को करीब एक महीना पहले ही भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था।

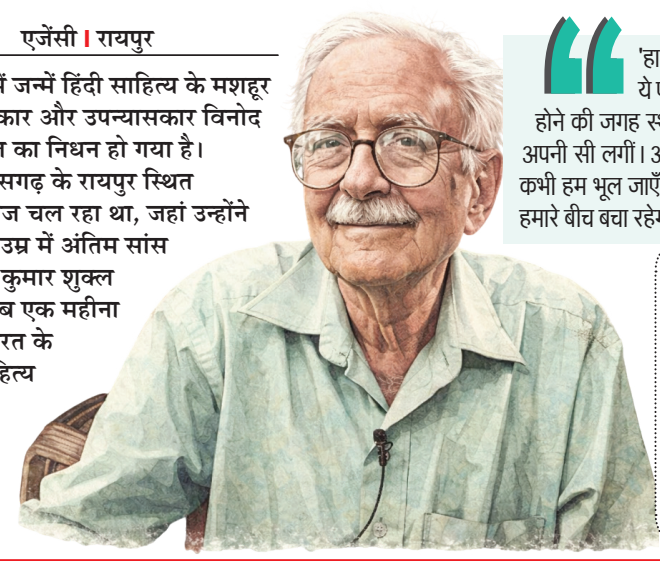

'हाथी चलता जाता था तो उसके पीछे हाथी के होने की जगह छूटती जाती थी...' ये पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल की है। विनोद कुमार शुक्ल चले गए। लेकिन उनके होने की जगह स्थाई रूप से छूट गई है...कभी न भरे जाने के लिए। इनकी पंक्तियाँ हमेशा अपनी सी लगीं। अब वे हमारे मन की दीवारों में एक खिड़की की तरह हमेशा रहेंगे जिसमें से कभी हम भूल जाएँगे, कभी वे चुपचाप झांक लिया करेंगे। विनोद कुमार शुक्ल का होना हमेशा हमारे बीच बचा रहेगा....श्रद्धांजलि बहुत प्रिय रचनाकार!

कवि, कथाकार और उपन्यासकार के रूप में समान रूप से प्रतिष्ठित

शुक्ल कवि, कथाकार और उपन्यासकार के रूप में समान रूप से प्रतिष्ठित रहे। उनकी पहली कविता 'लगभग जयहिंद' वर्ष 1971 में प्रकाशित हुई। उपन्यास 'नौकर की कमीज', 'दीवार में एक खिड़की रहती थी' और 'खिलेगा तो देखेंगे' को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है। 'नौकर की कमीज' पर प्रसिद्ध फिल्मकार मणिकौल द्वारा इसी नाम से फिल्म भी बनाई गई थी। वहीं 'दीवार में एक खिड़की रहती थी' को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। उनका लेखन प्रयोगधर्मी होने के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं और मध्यवर्गीय जीवन की सूक्ष्म परतों को बेहद सहज भाषा में अभिव्यक्त करता है।

लंबे समय से बीमार

शुक्ल लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें दो दिसंबर को एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन सपोर्ट के दौरान उन्होंने आज शाम को अंतिम सांस ली। हिंदी साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए वर्ष 2024 में उन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। वे इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित होने वाले हिंदी के 12वें साहित्यकार और छत्तीसगढ़ के पहले लेखक थे।

राजनांदगांव में हुआ था जन्म

शुक्ल का जन्म एक जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ था। उन्होंने अध्यापन को आजीविका के रूप में अपनाते हुए अपना संपूर्ण जीवन साहित्य सृजन को समर्पित किया। सादगी, मौलिकता और गहरी संवेदनशीलता उनके लेखन की पहचान रही। शुक्ल जी का पहला कविता संग्रह 'लगभग जयहिंद' है।

आवारा कुत्तों का उत्पात, नागरिकों में भय का माहौल

डीबीडी संवाददाता । उल्हासनगर

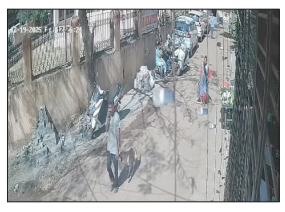

उल्हासनगर कैंप-3 के सेक्शन 20 स्थित गोल चक्र और गणेश नगर परिसर में आवारा और पालतू कुत्तों के हमलों से नागरिकों में डर का माहौल बन गया है। सेक्शन 20 और गोल चक्र क्षेत्र से सामने आए दो वीडियो ने शहरवासियों की चिंता और बढ़ा दी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आवारा कुत्ते पीछे से आकर अचानक सड़क पर चल रहे लोगों पर हमला कर उन्हें काट रहे हैं।

रोजाना हो रहे हमले, लोग सहमे

स्थानीय शिकायतकर्ताओं के अनुसार यह समस्या हाल-फिलहाल की नहीं है। लगभग रोज किसी न किसी नागरिक के कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। शिकायत में कहा गया है कि फिलहाल दो वीडियो उपलब्ध हैं, लेकिन इससे पहले भी इलाके में कई बार कुत्तों के हमले हो चुके हैं। सुबह और शाम के समय सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है, खासकर बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर लोगों में गहरी चिंता है।

मनपा से सख्त कार्रवाई की मांग

नागरिकों ने उल्हासनगर महानगरपालिका से मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आक्रामक आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी चिकित्सकीय जांच, टीकाकरण और नसबंदी अभियान तेज किया जाना जरूरी है। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से पहले स्थिति पर काबू पाया जा सके। निवासियों का साफ कहना है कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर कार्रवाई की आवश्यकता है।

ठाणे मनपा चुनाव

महायुति में खींचतान, एनसीपी ने जताई नाराजगी

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने ठाणे महानगरपालिका चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ महायुति में सीट बंटवारे पर नाराजगी जाहिर की है। पार्टी का कहना है कि उसे गठबंधन से जुड़ी अहम बैठकों से दूर रखा जा रहा है, जिससे महायुति के भीतर समन्वय की कमी उजागर हो रही है।

इस बयान के बाद गठबंधन में अंतर्कलह के संकेत और तेज हो गए हैं। एनसीपी प्रवक्ता आनंद परांजपे ने मंगलवार को कहा कि ठाणे मनपा चुनाव के लिए भाजपा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के स्थानीय नेता आपस में सीटों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राकांपा को इन बैठकों में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने इसे गठबंधन सहयोगियों के बीच तालमेल की कमी करार दिया।

गठबंधन को लेकर लचीला रुख

परांजपे ने यह भी कहा कि जहां संभव होगा, राकांपा महायुति के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय स्तर पर अन्य दलों के साथ गठबंधन या फिर स्वतंत्र रूप से मैदान में उतरने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। हाल ही में हुए 288 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों का हवाला देते हुए परांजपे ने कहा कि भाजपा, शिवसेना और राकांपा के गठबंधन ने करीब 215 निकायों में महापौर चुने हैं। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र की जनता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार पर भरोसा जताया है।

अकेले चुनाव लड़ने का विकल्प खुला

परांजपे ने स्पष्ट किया कि यदि राकांपा को सीट बंटवारे की बातचीत में शामिल नहीं किया गया, तो पार्टी ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने दावा किया कि ठाणे जिला राकांपा अध्यक्ष नजीब मुल्ला से अब तक न भाजपा और न ही शिवसेना ने कोई संपर्क किया है, जिसके चलते पार्टी अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुट गई है। एनसीपी प्रवक्ता के अनुसार, बीते दो दिनों में पार्टी ने करीब 380 इच्छुक उम्मीदवारों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि यदि गठबंधन में राकांपा को सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलती है, तो पार्टी महायुति के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार है। अन्यथा, राकांपा ठाणे महानगरपालिका की सभी 131 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है।

सोने की चेन चोरी के आरोपी गिरफ्तार

- 7 सोने की चेन चोरी के मामले सुलझाए गए

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

4 दिसंबर की रात लगभग साढ़े ग्यारह बजे, दो अनजान लोग स्कूटर से आए और स्कूटर चला रही 65 साल की महिला के गले से 60 ग्राम का सोने का मंगलसूत्र ज़बरदस्ती खींचकर भाग गए। घटना के बाद महिला सड़क पर गिर गई और घायल हो गई। राबोडी पुलिस स्टेशन में मामला 469/2025 भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 309 (6), 3(5) के तहत दर्ज किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्राइम ब्रांच इस केस को सुलझाने में जुटी हुई थी।

क्राइम ब्रांच, यूनिट-1, ठाणे की 12 दिन की लगातार जांच के बाद तकनीकी जानकारी के आधार पर मुंब्रा-शिलफाटा क्षेत्र में रहने वाले आरोपियों की पहचान हुई। 18 दिसंबर 2025 को जाल बिछाकर वसीम नूरमोहम्मद शेख (31, रूम 605, मिल्लत कॉम्प्लेक्स, मुंब्रा) और यासीन सिराज खामरे (22, रूम 705, हाजी उस्मान हाइट्स, मुंब्रा) को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया।

जब्त सामग्री और पिछले अपराधों का खुलासा

गिरफ्तार आरोपियों की जांच में पता चला कि उन्होंने ठाणे और नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में सोने की चेन चोरी के सात अन्य अपराध भी किए हैं। इस मामले में 118 ग्राम सोने के गहने, जिसकी कीमत लगभग 14,16,000/- रुपए है, और 60,000/- रुपए कीमत का जुपिटर मोटर स्कूटर जब्त किया गया। इस कार्यवाही में अपराध शाखा के उपायुक्त अमर सिंह जाधव, सहायक पुलिस आयुक्त शेखर बागड़े, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सचिन गायकवाड़, और अन्य अधिकारियों का मार्गदर्शन रहा।

एसवीईपी के तहत मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन

डीबीडी संवाददाता । वसई

वसई-विरार नगर निगम द्वारा ओम प्रकाश यादव नगर निगम क्षेत्र में एसवीईपी (Systematic Voters' Education and Electoral Participation) गतिविधि के अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। माननीय राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वसई-विरार नगर निगम आम चुनाव-2026 का कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है, जिसके तहत 15 जनवरी 2026 को मतदान होना है। इसी पृष्ठभूमि में नगर निगम ने मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एसवीईपी के तहत व्यापक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान का संदेश

मतदान लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और यह नागरिकों को देश व समाज की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार देता है। इसी संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए वार्ड समिति 'सी' चंदनसर द्वारा, माननीय आयुक्त श्री मनोज कुमार सूर्यवंशी (बी.पी.एस.) के निर्देशन एवं माननीय उपायुक्त श्री अजीत मुथे के मार्गदर्शन में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में वार्ड समिति कार्यालय व मुख्यालय के अधिकारी-कर्मचारी तथा विभिन्न विद्यालयों के छात्र शामिल हुए। मतदान के महत्व को दर्शाने वाले नारों के साथ विभिन्न क्षेत्रों से गुजरती इस रैली में स्कूली छात्रों की बैंड टीम ने भी भाग लेकर मतदाताओं का ध्यान आकर्षित किया। नगर निगम ने इस रैली के माध्यम से सभी नागरिकों से 15 जनवरी 2026 को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है, साथ ही यह स्पष्ट किया कि मतदान के दिन तक विभिन्न गतिविधियों के जरिए यह जागरूकता अभियान निरंतर जारी रहेगा।

भिवंडी-निजामपुर मनपा चुनाव

पहले ही दिन 456 नामांकन फॉर्म बिके, एक भी दाखिल नहीं

डीबीडी संवाददाता । भिवंडी

भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका के सार्वत्रिक चुनाव 2025-26 के तहत नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 23 दिसंबर 2025 को नामांकन फॉर्म बिक्री के पहले ही दिन कुल 456 फॉर्म खरीदे गए, हालांकि इस दौरान किसी ने भी नामांकन फॉर्म दाखिल नहीं किया।

मनपा प्रशासन के अनुसार, अलग-अलग निर्वाचन निर्णय अधिकारियों के कार्यालयों से नामांकन फॉर्म की बिक्री इस प्रकार रही: क्रमांक-1 से 28, क्रमांक-2 से 54, क्रमांक-3 से 133, क्रमांक-4 से 63, क्रमांक-5 से 60, क्रमांक-6 से 78 और क्रमांक-7 से 40। सभी कार्यालयों में नामांकन दाखिल की संख्या शून्य रही।

चुनावी सरगर्मी और तैयारियाँ

चुनावी जानकारों के अनुसार, पहले दिन बड़ी संख्या में फॉर्म खरीदे जाने से आगामी मनपा चुनाव में राजनीतिक गतिविधियों की तेज़ी का संकेत मिलता है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। मनपा प्रशासन ने चुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। अब सभी की निगाहें अगले चरण में कितने प्रत्याशी औपचारिक रूप से चुनावी मैदान में उतरते हैं, पर टिकी हैं।

भाजपा संगठन में नई नियुक्तियां

डीबीडी संवाददाता । भाईंदर

आगामी मनपा चुनाव में 'अबकी बार 70 पार' का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा और शिवसेना (शिंदे) के बीच वर्चस्व की जंग तेज हो गई है। विधायक नरेंद्र मेहता भाजपा को और अधिक मजबूत व सशक्त बनाने की दिशा में लगातार सक्रिय हैं। चुनावी तैयारियों के बीच बागियों को मनाना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इसी क्रम में जिला उपाध्यक्ष प्रसाद सुर्वे ने शिवसेना, जबकि संदीप तिवारी ने शिवसेना (उबाठा) का दामन थाम लिया है। मनपा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भाजपा शहर इकाई ने संगठन को मजबूती देने के लिए अहम नियुक्तियां की हैं। शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति और 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' सामाजिक संस्था के अध्यक्ष डॉ. अजय दूबे को भाजपा रियल एस्टेट सेल का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वहीं प्रवीण राय को भाजपा कामगार आघाड़ी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है।

संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का भरोसा

विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि नवनियुक्त दोनों जिलाध्यक्ष अनुशासन के साथ पार्टी की विचारधारा और जनसेवा के मूल्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि ये नियुक्तियां संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और आगामी मनपा चुनावों में पार्टी को लाभ पहुंचाएंगी।

जैसे घर लौट आए : सुर्वे

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की कार्यशैली से प्रभावित होकर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रसाद सुर्वे ने शिवसेना में प्रवेश किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिवसेना में शामिल होकर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वे अपने ही घर लौट आए हों। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि वे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के मार्गदर्शन में शहर में संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ कार्य करेंगे।

जंगल की बर्बादी और बेकाबू विकास की वजह से इंसान-तेंदुए का टकराव बढ़ा

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

महाराष्ट्र में इंसान और तेंदुए के बढ़ते टकराव को लेकर पर्यावरणविद डॉ. प्रशांत रवींद्र सिनकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने राज्य की वाइल्डलाइफ पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जंगलों की बर्बादी, बेकाबू शहरीकरण और बिना योजना के इंसानी दखल पूरे राज्य में इस संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। डॉ. सिनकर ने सीधे सवाल किया, 'जब कोई तेंदुआ इंसानी बस्ती में आता है तो उसे खतरा माना जाता है, लेकिन जब इंसान जंगल में घुसता है तो इसे विकास कैसे मान लिया जाता है?'

डॉ. सिनकर ने सरकार से जंगल सीमाओं पर प्लान्ड सेटलमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्डलाइफ़ के लिए बायोलॉजिकल कॉरिडोर बनाने

पर्यावरणविद डॉ. प्रशांत सिनकर का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र

और को-एग्जिस्टेंस पर आधारित अवेयरनेस प्रोग्राम लागू करने की मांग की। उनका मानना है कि तेंदुए को पकड़ना या जंगल से हटाना समस्या का समाधान नहीं है। 'तेंदुआ आईना है, जो दिखाता है कि हमने प्रकृति के साथ क्या किया। यदि जंगल नहीं बचाए गए, संघर्ष कभी नहीं रुकेगा।'

जंगलों पर दबाव और समाज की जिम्मेदारी

डॉ. सिनकर ने कहा कि महाराष्ट्र के जंगल अब प्रोजेक्ट्स, अतिक्रमण, सड़कें, रेलवे, लाइट और नॉइज़ पॉल्यूशन, और कचरे की चपेट में हैं। उनका कहना है कि हम जंगल को मैप से मिटा चुके हैं और जंगल से भागे तेंदुए को दोषी ठहरा रहे हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बच्चों या माताओं को नुकसान होते देखना दुखद है, लेकिन तेंदुए की आंखों में डर और भ्रम देखकर भी समाज को संवेदनशील होना चाहिए।

कंपनी के कैंपस में मर्डर

डीबीडी संवाददाता । पालघर

पालघर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने आपसी विवाद के चलते अपने ही ऑफिस के सहकर्मी की हत्या कर दी और शव को कंपनी परिसर में स्थित पानी की टंकी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

घटना वसई इलाके के एक औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को हुई। आरोपी की पहचान 27 साल के आसाराम राकेश के रूप में हुई है, जबकि मृतक का नाम राकेश सिंह बताया गया है। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे।

प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी और मृतक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।

बहस के बाद साथ काम करने वाले ने ले ली जान, पानी की टंकी में फेंकी लाश

गुस्से में आकर आसाराम ने कथित तौर पर लोहे की रॉड से अपने सहकर्मी पर हमला किया। हमले के बाद आरोपी ने सबूत छिपाने की नीयत से शव को कंपनी परिसर में बनी पानी की टंकी में डाल दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब अन्य कर्मचारियों को संदिग्ध गतिविधियों का पता चला और उन्होंने तुरंत पुलिस और मृतक के परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

पुलिस कार्रवाई और जांच

पालघर पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही आरोपी को कुछ ही घंटों में हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि विवाद की असली वजह क्या थी और क्या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी। कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों से भी पूछताछ जारी है।

बोईसर में गांजा के साथ महिला गिरफ्तार

डीबीडी संवाददाता । पालघर

पालघर जिले की बोईसर पुलिस ने अवैध रूप से गांजा रखने और तस्करी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील जाधव के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बोईसर-तारापुर मार्ग पर एक ऑटो रिक्शा में गांजे की तस्करी हो रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने बोईसर एसटी बस डिपो के सामने नाकाबंदी कर संदिग्ध ऑटो रिक्शा को रोका। संदिग्ध रिक्शा में सवार महिला संगीता शिवबहादुर सिंह के सामान की तलाशी लेने पर लगभग 2.9 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजा जब्त कर महिला को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ बोईसर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील जाधव की अगुवाई में पुलिस उपनिरीक्षक नितिन नरले और उनकी टीम ने यह कार्रवाई सफलतापूर्वक अंजाम दी। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गांजा कहां से लाया गया और इसे कहां ले जाया जाना था।

वसई-विरार महानगरपालिका चुनाव

जनता कांग्रेस 115 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

ओपी यादव । विरार

वसई-विरार महानगरपालिका के आगामी चुनाव में जनता कांग्रेस पार्टी ने सभी 115 वार्डों में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए 50 प्रतिशत मुस्लिम, 25 प्रतिशत दलित और 25 प्रतिशत श्रमण (शोषित-वंचित वर्ग) उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। पार्टी का दावा है कि यह प्रतिनिधित्व वसई-विरार की सामाजिक संरचना को सही मायनों में प्रतिबिंबित करेगा।

वसई-विरार महानगरपालिका पर लगभग 35 वर्षों तक बहुजन विकास आघाड़ी का शासन रहा है, जबकि हाल के वर्षों में इस क्षेत्र से भाजपा के सांसद और विधायक निर्वाचित हुए हैं। इसके बावजूद आज भी शहर की जनता बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी से जूझ रही है। खराब सड़कें, पेयजल की समस्या, अव्यवस्थित गटर लाइन, अस्थिर बिजली व्यवस्था और मनपा के अधीन एक भी ढंग का स्कूल न होना स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इन समस्याओं के समाधान और वसई-विरार को एक सुव्यवस्थित, स्वच्छ और जन-हितैषी शहर बनाने के उद्देश्य से जनता कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. महताब राय ने स्पष्ट कहा है कि 'अब वसई-विरार को बदलने का वक्त आ चुका है' और यह बदलाव केवल जनता कांग्रेस ही ला सकती है।

घोषणापत्र नहीं, शपथपत्र देने का वादा

महाराष्ट्र प्रदेश जनता कांग्रेस अध्यक्ष शैलेश पावसकर ने कहा कि पार्टी पिछले पांच वर्षों से लगातार जनता के बीच रही है और हर समस्या के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाती रही है। उन्होंने दावा किया कि यदि जनता कांग्रेस को सत्ता मिलती है और पार्टी का महापौर बनता है, तो वसई-विरार की कोई भी मूलभूत समस्या शेष नहीं रहेगी। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि जनता कांग्रेस का चुनावी घोषणापत्र केवल कागजी दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि एफिडेविट के रूप में जनता के सामने रखा जाएगा, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

टीएमसी की 9 वार्ड समितियों में 1069 नामांकन पत्र बांटे गए

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

ठाणे महानगर पालिका आम चुनाव 2025 के लिए नामांकन पत्र बांटने का काम आज से शुरू हो गया है। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 9 वार्ड कमेटियों के उम्मीदवारों को कुल 1069 नामांकन पत्र वितरित किए गए। माझीवाडा मानपाड़ा वार्ड कमेटी के तहत वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 8 के लिए 157 नामांकन पत्र बांटे गए। वर्तकनगर वार्ड कमेटी के वार्ड 4, 5 और 7 के लिए 103

आवेदन पत्र वितरित किए गए। लोकमान्यनगर सावरकर वार्ड कमेटी के वार्ड 6, 13, 14 और 15 के लिए 177 नामांकन पत्र और वागले वार्ड कमेटी के वार्ड 16, 17 और 18 के लिए 102 नामांकन आवेदन वितरित किए गए।

अन्य वार्ड कमेटियों में भी किया गया वितरण

नौपाड़ा कोपरी वार्ड कमेटी के वार्ड 19, 20, 21 और 22 के लिए 113 आवेदन पत्र, उथलसर वार्ड कमेटी के वार्ड 10, 11 और 12 के लिए 101 आवेदन पत्र और कलवा वार्ड कमेटी के वार्ड 9, 23, 24 और 25 के लिए 121 नामांकन पत्र बांटे गए। मुंब्रा और दीवा वार्ड कमेटियों के तहत भी सभी संबंधित वार्डों में कुल 195 और 124 नामांकन फॉर्म वितरित किए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने इस प्रक्रिया की जानकारी दी।

माल्या के भारत लौटने पर ही उसकी याचिका पर होगी सुनवाई

- बॉम्बे हाई कोर्ट ने विजय माल्या को भारत लौटने का दिया निर्देश
- 12 फरवरी 2026 को मामले की अगली सुनवाई

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार (23 दिसंबर) को एक बार फिर भगोड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या के वकीलों को निर्देश दिया कि माल्या को भारत लौटना चाहिए। अदालत ने साफ किया कि उनके भारत लौटने की स्थिति स्पष्ट किए बिना उनकी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई संभव नहीं है और उनमें से एक को वापस लेना होगा। जब कोर्ट ने याचिकाओं में से एक वापस लेने को कहा, तो विजय माल्या के वकील अमित देसाई ने अतिरिक्त समय की मांग की। इस पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 फरवरी 2026 तक के लिए टाल दी और निर्देश दिया कि अगली तारीख पर वकील अपनी स्थिति स्पष्ट करें

संपत्ति जब्ती और कर्ज चुकाने का दावा

माल्या का आरोप है कि जांच एजेंसियों ने उनके कर्ज से अधिक मूल्य की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि ब्याज सहित कर्ज की राशि करीब 15,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है, जिसे वे अपनी संपत्तियां बेचकर चुकाने को तैयार हैं। हालांकि, उनके सभी खाते और संपत्तियां जांच एजेंसियों के नियंत्रण में होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं।

केंद्र सरकार और ईडी का विरोध

केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माल्या की याचिका का विरोध करते हुए इसे खारिज करने की मांग की है। ईडी का तर्क है कि नया कानून ऐसे आर्थिक अपराधियों को रोकने के लिए लाया गया है, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए विदेश भाग जाते हैं। हालांकि, ईडी ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून में प्रावधान है कि यदि विशेष अदालत आरोपी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं मानती, तो जब्त संपत्ति वापस की जा सकती है।

प्रत्यर्पण प्रक्रिया अंतिम चरण में

भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर विदेश भागे विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत लाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऐसे में केंद्र सरकार को आशंका है कि माल्या ब्रिटिश अदालतों में कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर सकता है। इसी आधार पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट से माल्या की याचिका खारिज करने की मांग की।

चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने स्पष्ट कहा कि आर्थिक अपराध कर विदेश भागे लोग वहां बैठकर भारतीय अदालतों में याचिकाएं दायर नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि पहले यह बताया जाए कि वे भारत कब लौटेंगे, तभी उनकी याचिकाओं पर विचार किया जाएगा। अदालत ने यह भी साफ किया कि संतोषजनक जवाब मिलने तक किसी भी कानूनी कार्रवाई पर रोक नहीं लगेगी। विजय माल्या ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्हें 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किए जाने को चुनौती दी है। उनका दावा है कि इस कानून के तहत उन्हें "फाइनेंशियल डेथ सेंटेंस" दिया गया है।

नमोकार तीर्थ बनेगा देश का प्रमुख जैन केंद्र

- फडणवीस सरकार ने 36 करोड़ की योजना को दी मंजूरी

मुंबई/नासिक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक जिले के मलसाने गांव स्थित जैन तीर्थ स्थल नमोकार तीर्थ के विकास के लिए 36.35 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। परियोजना का उद्देश्य तीर्थयात्रियों को सुविधाजनक और संतोषजनक अनुभव देना है। अधिकारियों के अनुसार, यह योजना तीर्थस्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है।

उच्च गुणवत्ता और समयबद्ध कार्य

आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्य उच्च गुणवत्ता का हो और तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि कोई भी समझौता मानकों के साथ नहीं होना चाहिए।

तीर्थस्थल पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तीर्थयात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। परियोजना का लक्ष्य न केवल आध्यात्मिक संतुष्टि बल्कि तीर्थस्थल पर आंतरिक संतोष सुनिश्चित करना है।

अंतरराष्ट्रीय पंचकल्याणक उत्सव

नासिक जिले के चंदवाड तालुका के मलसाने गांव में स्थित नमोकार तीर्थ में 6 से 25 फरवरी, 2026 तक अंतरराष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठान उत्सव आयोजित होने वाला है। अधिकारियों के अनुसार, इस दौरान देश-विदेश से लगभग 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। स्वीकृत कुल राशि में से 24.26 करोड़ रुपये स्थायी अवसंरचना कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। वहीं, 12.09 करोड़ रुपये उत्सवों से संबंधित व्यवस्थाओं जैसे सुरक्षा, आवास और परिवहन पर खर्च किए जाएंगे।

न्यूज ब्रीफ

80 लाख की अंबरग्रीस के साथ आरोपी गिरफ्तार

मुंबई। कुर्ला इलाके में पुलिस ने व्हेल की उल्टी (अंबरग्रीस) की अवैध बिक्री के प्रयास को नाकाम करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से करीब 80 लाख रुपये मूल्य की अंबरग्रीस जब्त की गई है। वन विभाग से मिली गुप्त सूचना के आधार पर कुर्ला पुलिस और वन अधिकारियों की संयुक्त टीम ने एलबीएस रोड पर जाल बिछाकर संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसकी तलाशी के दौरान बैग से अंबरग्रीस बरामद हुई।

आरोपी की पहचान गुजरात निवासी विष्णुभाई मकवाना के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है, जिसमें यह पता लगाया जा रहा है कि अंबरग्रीस कहां से लाई गई थी और इसके पीछे किसी बड़े तस्करी नेटवर्क का हाथ तो नहीं है।

महाराष्ट्र के डीजीपी बनाए जा सकते हैं एनआईए प्रमुख सदानंद दाते

मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) प्रमुख सदानंद वसंत दाते महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बनाए जा सकते हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी को केंद्र ने वापस उनके मूल कैडर महाराष्ट्र भेज दिया है। वह मार्च 2024 से एनआईए महानिदेशक के पद पर तैनात थे। महाराष्ट्र की वर्तमान डीजीपी रश्मि शुक्ला जनवरी में सेवानिवृत हो रही हैं। सदानंद उनके बाद राज्य के दूसरी वरिष्ठ आईपीएस हैं। सदानंत वसंत दाते 26/11 मुंबई आतंकी हमले में वीरता दिखाने के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित हो चुके हैं। तब वह महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख थे। सदानंद वसंत दाते सीबीआई में डीआईजी और सीआरपीएफ में आईजी रह चुके हैं।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर मौतों में 26% की कमी

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर जनवरी से नवंबर 2025 के बीच सड़क दुर्घटनाओं में मौतों में 26 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

परिवहन विभाग के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में एक्सप्रेसवे पर 54 दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें 61 लोगों की मौत हुई, जबकि 2024 में इसी अवधि में 66 दुर्घटनाओं में 82 लोगों की जान गई थी।

विभाग के अधिकारी ने कहा कि यह कमी सड़क सुरक्षा उपायों और जागरूकता अभियानों के कारण संभव हुई है। राज्यव्यापी स्तर पर भी सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या में 119 की कमी आई है, हालांकि कुल दुर्घटनाओं में मामूली वृद्धि हुई। आंकड़े यह संकेत देते हैं कि दुर्घटनाओं की गंभीरता में सुधार हुआ है और सुरक्षा पहल प्रभावी रही हैं।

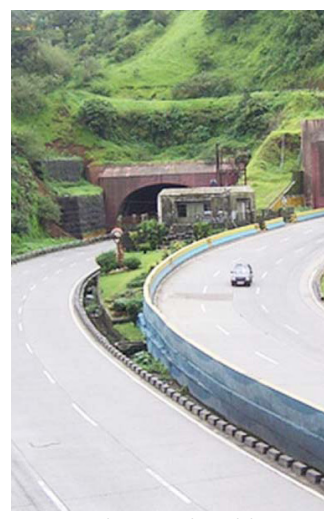

एसआरए के खिलाफ टैक्सी ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन

दीपक पवार | मुंबई

मुंबई के वर्ली इलाके में टैक्सी ड्राइवरों और स्थानीय निवासियों ने स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) के प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बहुजन शक्ति टैक्सी ड्राइवरों और वर्ली निवासियों की ओर से यह आंदोलन 25 वर्षों से रुकी हुई 'इंदिरा' एसआरए स्कीम को तत्काल शुरू करने की मांग को लेकर किया गया। इस दौरान संगठन ने एसआरए के सीईओ डॉ. महेंद्र कल्याणकर को ज्ञापन सौंपकर लंबित प्रोजेक्ट को जल्द पूरा कर निवासियों को उनका हक दिलाने की मांग की।

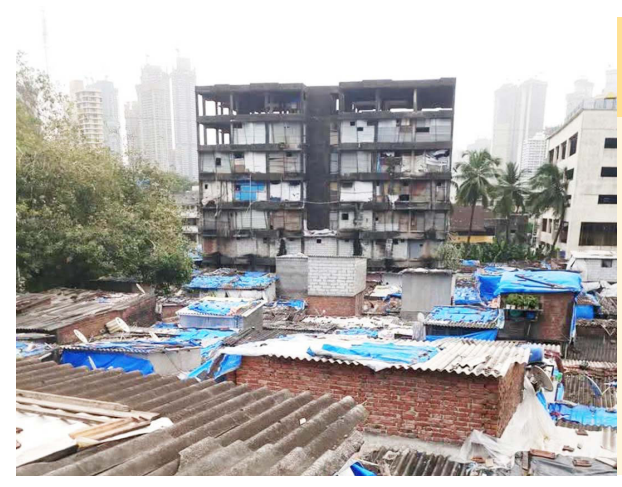

25 साल बाद भी अधूरी 'इंदिरा' एसआरए स्कीम

वर्ली नाका के प्रेमनगर और सिद्धार्थनगर क्षेत्र में स्थित इंदिरा एसआरए को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्ष 2002-03 में शुरू की गई थी, जिसके तहत उस समय झुग्गियां खाली कराई गई थीं। लेकिन करीब 25 साल बीत जाने के बावजूद यह परियोजना पूरी नहीं हो सकी है। इसके चलते कई टैक्सी ड्राइवर और निवासी आज भी किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं। निवासियों का आरोप है कि संबंधित डेवलपर ने इतने वर्षों में एक भी महीने का किराया नहीं दिया।

आंदोलन की चेतावनी, सख्त कार्रवाई की मांग

निवासियों ने यह भी चिंता जताई कि आधी-अधूरी इमारत खड़ी होने से सुरक्षा का खतरा बना हुआ है, जबकि असली बिल्डिंग का काम कब पूरा होगा, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही। बहुजन शक्ति टैक्सी ड्राइवर ओनर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मांग की है कि एसआरए प्रोजेक्ट को रोकने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और निर्माण कार्य तुरंत शुरू कराए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा।

48 करोड़ रुपए का हाइड्रोपोनिक गांजा ज़ब्त, 8 गिरफ्तार

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई कस्टम्स टीम ने छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) पर आठ यात्रियों से 48 किलो से अधिक हाइड्रोपोनिक वीड और इसकी कुल कीमत 48 करोड़ रुपये से अधिक की ज़ब्ती की है। यह कार्रवाई कस्टम्स एयरपोर्ट कमिश्नरेट की टीम द्वारा 18 से 22 दिसंबर के बीच ऑपरेशन के दौरान की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रोफाइलिंग और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर बैंकॉक और मस्कट से आने वाले यात्रियों को हिरासत में लिया गया।

ड्रग्स छिपाने के तरीके और बरामदगी

कस्टम्स टीम ने अलग-अलग मामलों में यात्रियों से शैम्पू की बोतलों और टिन स्नैक बॉक्स में छिपाए गए नशीले पदार्थ बरामद किए। बैंकॉक से यात्रा कर रहे पांच यात्रियों से कुल 35.045 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला, जिसकी कीमत लगभग 35 करोड़ रुपये बताई गई। वहीं, मस्कट से आए एक यात्री के पास से 16.2 लाख रुपये कीमत की 81 ग्राम एम्फैटेमिन बरामद हुई।

अन्य मूल्यवान ज़ब्ती और गिरफ्तारी

ऑपरेशन के दौरान कस्टम्स टीम ने 35.18 लाख रुपये कीमत के 283 ग्राम हीरे के गहने और 6.6 किलो पॉलिश किए हुए सेमी-प्रीशियस पत्थर (24.91 लाख रुपये मूल्य) भी जब्त किए। इसके अलावा, 22 दिसंबर को फुजैराह जा रहे यात्रियों से 45.26 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा बरामद हुई। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है।

मुंबई में कोई मामू और खान महापौर नहीं बनेगा : संजय निरुपम

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र में हाल के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में शिवसेना ने जनता का पूरा भरोसा हासिल किया है। शिवसेना के उपनेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया कि शिवसेना की ताकत किसी और के सहारे नहीं बल्कि जनता के समर्थन से है। उन्होंने बताया कि जहां उबाठा सिंगल डिजिट तक भी नहीं बढ़ पाए, वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।

बीएमसी चुनाव में उबाठा और कांग्रेस पर हमला

संजय निरुपम ने बीएमसी चुनाव को लेकर उबाठा गुट और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब ये पार्टियां साथ रही हैं, तब मुंबई और महाराष्ट्र में गंभीर घटनाएं हुई हैं।

मध्य रेल
भुसावल मंडल
ई-निविदा सूचना संख्या
बीएसएल-टीआरएस-टेंडर-2025-15
दि. 22/12/2025
(1) कार्य का विवरण: ELS/BSL के WAP-4 लोकोमोटिवों की फ्लेक्सी-कॉयल उच्च गति बोल्स्टर प्रकार बोगी फ्रेम का ओवरहॉलिंग कार्य। **(2) अनुमानित लागत:** रु. 70,78,830/- **(3) निविदा बंद होने की दिनांक एवं समय:** 17/01/2026 को 14:00 बजे। **4)** निविदा दस्तावेज़ की विस्तृत सूचना और विस्तृत निविदा शर्तों के लिए वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर देखें।
व.मं.वि.इं. (कचस्टा), भुसावल 04
अपने जानवरों को रेल लाइन से दूर रखे

उबाठा के लिए मुंबई सिर्फ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी : एकनाथ शिंदे

- शिवसेना के नवनिर्वाचित नगरसेवकों और नगराध्यक्षों का एकनाथ शिंदे के हाथों सम्मान

मुंबई। शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उबाठा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पिछले पच्चीस सालों तक सत्ता में रही उबाठा के लिए मुंबई सिर्फ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी। कोविड काल में हुए खिचड़ी घोटाले, फर्जी कोविड सेंटर और बॉडी बैग जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए शिंदे ने कहा कि आलोचना करने से पहले विरोधियों को खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। शिवसेना के नवनिर्वाचित नगराध्यक्षों का उपमुख्यमंत्री शिंदे ने मुंबई के स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक में सम्मानित किया। इस अवसर पर शिंदे ने कहा कि शिवसेना ने हमेशा विकास, जनसेवा और आम आदमी के हितों को प्राथमिकता दी है। समारोह में मंत्री, विधायक, पदाधिकारी, नगराध्यक्ष, नगरसेवक और बड़ी संख्या में शिवसैनिक उपस्थित थे।

धनुष्य-बाण की ताकत और जनता का आभार

नगर परिषद चुनावों के परिणामों पर शिंदे ने कहा कि शिवसेना का विस्तार अब महाराष्ट्र के हर कोने तक हुआ है। मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में शिवसेना का स्ट्राइक रेट सबसे अधिक रहा। राज्य में अब तक 62 नगराध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, जिनमें ** लाडली बहनें शामिल हैं, और यह संख्या जल्द ही 70 तक पहुँच जाएगी।

उबाठा और महाविकास आघाड़ी पर निशाना

शिंदे ने उबाठा और महाविकास आघाड़ी पर कटाक्ष किया और कहा कि नगर परिषद चुनाव में उबाठा पहले ही हार मान चुकी थी। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के नगराध्यक्षों की तुलना शिवसेना से करते हुए कहा कि शिवसेना की जमीन से जुड़ी मजबूती और आम लोगों के साथ अटूट संबंध इसे हराना नामुमकिन बनाते हैं।

मुख्य कार्यालय, विरार
विरार (प.), ता.वसई, जि. पालघर,
पिन-४०१ ३०३.

दुरध्वनी : ०२५०-६६३०००० / २५२७१०८
टोल फ्री क्र. : १८००२३३४३५३
ई-मेलः vasaivirarcorporation@yahoo.com
जा.क्र : वविशम/मु.विद्युत/११३९/२०२५
दिनांक : 22/12/2025

निविदा मागविण्याची सूचना (RFP) (प्रथम मुदतवाढ)
(टेंडर आयडी क्र. २०२५_VVCMC_१२५९७५६_१)

विषय :- महानगरपालिका **कार्यक्षेत्रातील रहदारी व वाहतुक नियंत्रण करणेकरिता एकत्रित कमान्ड अँन्ड कंट्रोल सेंटर (ICCC), CCTV यंत्रणा, ऑप्टीकल फायबर कम्युनिकेशन नेटवर्क (OFC), ट्रॅफिक सिग्नल कंट्रोल यंत्रणा (ATSC), प्रोजेक्टची रचना, विकास, व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणी करिता प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) यांची नियुक्ती करणे कामाचे स्वारस्य दर्शविणारे पत्रास (EoI) प्रथम मुदतवाढ देणे बाबत...**

याद्वारे कळविण्यांत येते की, उपरोक्त विषयांकीत कामी जा.क्र.वविशम/मु.विद्युत/११०९/२०२५, दि.१२/१२/२०२५ रोजीचे स्वारस्य दर्शविणारे पत्राची (EoI) मुदत खालीलप्रमाणे वाढविण्यात आलेली आहे. अधिक माहिती करीता विद्युत विभाग, मुख्यालय, विरार (प.) येथे संपर्क साधावा.

१) निविदा खरेदी व प्रिपरेशन अंतिम दिनांक	-दि.३०/१२/२०२५ रोजी स.११.०० वाजेपर्यंत
२) निविदा स्विकृती दिनांक	-दि.३०/१२/२०२५ रोजी स. ११.०० वाजेपर्यंत
३) निविदा उघडणेची दिनांक	-दि.०१/०१/२०२६ रोजी स.११.०० वा. अथवा इतर सोयीच्या दिवशी

तरी बदल झालेल्या तारखांची नोंद घ्यावी.

सही/-
(दिपक सावंत)
अतिरिक्त आयुक्त (उत्तर)
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

संपादकीय

समता में ही न्याय

आय और संपत्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण आज भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानता की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद, हाशिए पर पड़े वर्ग को बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच नहीं मिल पाती। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों में असमानता, समाज के निचले तबकों को पिछड़ने पर मजबूर कर रही है। हालिया 'विश्व असमानता रिपोर्ट, 2026' के अनुसार, भारत की कुल संपत्ति का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा शीर्ष 10 प्रतिशत अमीरों के पास है, जबकि निचले 50 प्रतिशत लोगों के पास केवल 6.4 प्रतिशत संपत्ति है। महिला श्रम भागीदारी दर भी केवल 15.7 प्रतिशत है, जो लैंगिक असमानता का स्पष्ट संकेत है। वहीं, देश के शीर्ष 1 प्रतिशत लोगों के पास देश की 40 प्रतिशत से अधिक संपत्ति केंद्रित है, जो 1961 के बाद का सबसे उच्च स्तर माना गया है। देश की आय असमानता भी चिंताजनक है। शीर्ष 10 प्रतिशत लोग राष्ट्रीय आय का 58 प्रतिशत अर्जित करते हैं, जबकि नीचे के 50 प्रतिशत लोगों को मात्र 15 प्रतिशत आय मिलती है। 2014 से 2024 के बीच इस अंतर में मामूली वृद्धि हुई, जो 38 प्रतिशत से बढ़कर 38.2 प्रतिशत हो गया। औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग 6,200 यूरो और औसत संपत्ति लगभग 28,000 यूरो मानी गई है। रिपोर्ट भारत को विश्व के सबसे असमान देशों में शुमार करती है। सर्वेक्षण और सरकारी आंकड़े भी यह तथ्य उजागर करते हैं कि देश में 41.32 प्रतिशत लोगों को आज भी आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि 31.52 प्रतिशत आबादी संतुलित पोषण से वंचित है। उपभोक्ता बाजार में प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती मांग और अफोर्डेबल रियल एस्टेट सेगमेंट की गिरावट भी असमानता की ओर इशारा करती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आय और संपत्ति का केंद्रीकरण आम नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर रहा है। भारत में असमानता के कई सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। उन्नत और पिछड़े राज्यों के बीच विकास का अंतर, विस्थापन के कारण लोगों की आजीविका और अधिकारों की हानि, भूमि स्वामित्व में असमानता, कृषि में अक्षमताएं, और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, ये सभी कारक ग्रामीण आय और जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। देश की बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में कम मजदूरी और अस्थिर रोजगार पर कार्यरत है, जहां कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच वेतन का भारी अंतर देखने को मिलता है। वैश्वीकरण ने भी असमानता को बढ़ावा दिया है। विनिर्माण क्षेत्र में बाधाएं और सेवा क्षेत्र में लाभ का कुछेक वर्गों तक सीमित होना लाखों लोगों को रोजगार के अवसरों से वंचित करता है। अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता गरीबों पर अतिरिक्त बोझ डालती है, जबकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि उनकी वास्तविक आय को और घटा देती है। भारत में आय असमानता के मुख्य कारणों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक असमान पहुंच, रोजगार के अवसरों में अंतर, कौशल और वेतन में खाई, क्षेत्रीय असंतुलन, जाति-लिंग आधारित भेदभाव और धन का केंद्रीकरण शामिल हैं। मुद्रास्फीति, अप्रभावी सरकारी नीतियां और संसाधनों का असमान वितरण इस अंतर को और गहरा कर देते हैं। असमानता केवल आर्थिक समस्या नहीं है; यह समाज की स्थिरता और राष्ट्रीय विकास पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई सामाजिक असंतोष, पारस्परिक द्वेष और संघर्ष को जन्म देती है। राजनीतिक दलों द्वारा आर्थिक और सामाजिक समता के दावों को अक्सर चुनावी रणनीति तक सीमित पाया गया है। समाज में संतुलित विकास और सामाजिक न्याय की अवधारणा तभी पूर्ण रूप से लागू हो सकती है जब समतामूलक समाज की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। समतावादी समाज का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार, अवसर और संसाधन प्राप्त हों। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए धन के पुनर्वितरण, संपत्ति कर और सुपर टैक्स जैसे उपाय अपनाने आवश्यक हैं। इसके अलावा, शिक्षा और स्वास्थ्य में समानता, रोजगार के अवसरों का सृजन, क्षेत्रीय विकास में संतुलन और महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा।

भरोसे और भविष्य की सौगात

कांतिलाल मांडोत
वरिष्ठ पत्रकार,
साहित्यकार-स्तम्भकार

राजस्थान की राजनीति और कृषि परिदृश्य में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन एक ऐतिहासिक पड़ाव बनकर सामने आया, जहाँ सरकार ने न केवल किसानों के लिए हजारों करोड़ रुपये की सौगातों का ऐलान किया, बल्कि बीते वर्षों की नीतियों, भ्रष्टाचार के आरोपों और भविष्य की दिशा को लेकर स्पष्ट संदेश भी दिया। इस सम्मेलन में मंच पर मौजूद नेताओं के भाषणों, भावनात्मक संवादों और ठोस घोषणाओं ने यह संकेत दिया कि राजस्थान में किसान और युवा सरकार की प्राथमिकता के केंद्र में हैं। सम्मेलन में कुल 3200 करोड़ रुपये से अधिक की सौगातों की घोषणा की गई, जिसने किसानों और ग्रामीण समाज में नई उम्मीद जगाई। राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ीमल मीणा ने अपने संबोधन में स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान किसानों के नाम पर जो 198 करोड़ रुपये बकाया थे, उन्हें वर्तमान सरकार ने अदा किया है। उन्होंने इसे किसानों के प्रति सरकार की जवाबदेही और ईमानदारी का प्रमाण बताया। उनका कहना था कि सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं करती, बल्कि जमीन पर उतारने का काम भी करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किरोड़ीमल मीणा ने बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार ने किसानों को 6,229 करोड़ रुपये देने का काम किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यह राशि उन किसानों के लिए संजीवनी साबित हुई है, जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं, मौसम की मार या अन्य कारणों से खराब हुईं। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना का उद्देश्य केवल मुआवजा देना नहीं, बल्कि किसान को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाना है। अपने भाषण के दौरान किरोड़ीमल मीणा ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं गंगानगर जाकर भ्रष्टाचार के मामलों को पकड़ा है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके शब्दों में तीखापन था, जब उन्होंने कहा कि 'मुंह से खाया हुआ नाक से निकालेंगे', जो यह दर्शाता है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। उनके इस बयान पर सम्मेलन में मौजूद किसानों और कार्यकर्ताओं ने तालियों के साथ समर्थन जताया। इस राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी सम्मेलन में पहुंचीं, जो यह दर्शाता है कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी इस बात का संकेत है कि सरकार की योजनाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। किरोड़ीमल मीणा ने अपने संबोधन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ अपने आत्मीय संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा कि 'मामा से काम करवाना मेरी जिम्मेदारी है'। यह संवाद मंच पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आया और राजनीति में मानवीय रिश्तों की झलक भी दिखी। शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने अंदाज में किसानों से संवाद किया और भावनात्मक शब्दों से उनका दिल जीत लिया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये की स्वीकृति की घोषणा की गई, जिससे ग्रामीण इलाकों में सड़क नेटवर्क मजबूत होगा और किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी। इसके अलावा नागौर जिले के लिए 351 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। कृषि और उद्यानिकी योजनाओं के तहत कुल 31 हजार 600 करोड़ रुपये के प्रावधान की जानकारी भी दी गई। इनमें से किसानों को विभिन्न मदों में 200 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। किसान अनुदान योजना के अंतर्गत 5 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा की गई, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 हजार 500 लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपये की सहायता दी गई, जो ग्रामीण आवास के क्षेत्र में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री सम्बल योजना के अंतर्गत 4.50 लाख पशुपालकों को 200 करोड़ रुपये की सौगात दी गई, जिससे पशुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में युवाओं को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार युवाओं के साथ है और युवाओं के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि हमने युवाओं से कहा था कि हम धोखा देने वालों को नहीं छोड़ेंगे।उन्होंने यह भी ऐलान किया कि राज्य में चार लाख नौकरियां दी जाएंगी और युवाओं से मेहनत करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेपर लीक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों में कई पेपर लीक हुए, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि उनकी सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। यह बयान युवाओं के बीच भरोसा पैदा करने वाला था और सरकार की प्रशासनिक सख्ती को दर्शाता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं और उनके सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पगड़ी का मान, आपका सम्मान और किसानों की शान कभी जाने नहीं दूंगा। उनके शब्दों में भावनात्मक गहराई थी, जिसने किसानों के दिलों को छू लिया। उन्होंने किसानों के संघर्ष, उनकी मेहनत और देश के विकास में उनके योगदान को नमन किया। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी घोषणा की कि केंद्र सरकार एक नया पेस्टिसाइड एक्ट ला रही है, जिससे नकली बीज और कीटनाशक बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि नकली बीज और कीटनाशक किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा हैं और सरकार इस पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है।

जीवन मंत्र

कैसा हो ईश्वर से रिश्ता

'ईश्वर हमारे हैं' का क्या अर्थ है? यह अनुभव करना कि ईश्वर और समस्त सृष्टि आपकी अपनी ही है। यह कोई बाजार की हड़बड़ खरीदारी नहीं- अक्सर हम जल्दबाजी में खरीदारी करते हैं, तो वापस घर आने की जल्दी में रहते हैं।

आप ईश्वर के पास जाते हो, आपको वरदान मिलता है और आप चले आते हो। जब आपका उद्देश्य केवल कोई वरदान पाने का होता है, तब आप जल्दी में होते हो। जो व्यक्ति जानता है कि ईश्वर उसके हैं, उसे किसी चीज की जल्दी नहीं होती। उसमें असीम धैर्य होता है। जब आप जानते हो कि ईश्वर आपके अपने हैं, तब आपको ईश्वर से कुछ लेने की जल्दबाजी नहीं होती। जल्दी से जल्दी कुछ पाने की चाह आपको डगमगा देती है, आपको छोटा बनाती है। इसलिए असीम धैर्य रखो। जब आपमें असीम धैर्य होगा, तब समझ सकोगे कि ईश्वर आपके ही हैं। या तो सजगता द्वारा या साधना से, आप इसे अनुभव करते हो। 'ईश्वर हमारे हैं' का क्या अर्थ है? यह अनुभव करना कि ईश्वर और समस्त सृष्टि आपकी अपनी ही है। यह कोई बाजार की हड़बड़ खरीदारी नहीं- अक्सर हम जल्दबाजी में खरीदारी करते हैं, तो वापस घर आने की जल्दी में रहते हैं। जब आप यह देखते हो कि बाजार की सभी वस्तुएं घर पर ही हैं, तब आप जल्दी में नहीं रहते, आप आराम से रहते हो। जब आप जान जाते हैं कि आप दैवीय विधि- विधान के हिस्से हैं, तब मांगना बंद कर देते हैं। आप जान जाते हैं कि सबकुछ आपके लिए ही किया जा रहा है, आपका ख्याल रखा जा रहा है। अपना धैर्य बढ़ाने के लिए आपको केवल अधीरता को देखना है। अपने

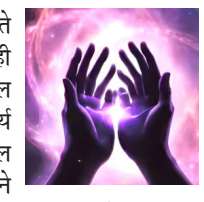

विचारों और अपनी भावनाओं पर ध्यान दो, उन पर पश्चाताप न करो। सामान्यतः हम दिमाग को दौड़ाते हैं और काम करने में सुस्ती दिखाते हैं। अधीरता का अर्थ ही है दिमाग की जल्दबाजी; आलस्य का अर्थ है कार्य में सुस्ती। मन में धैर्य और कार्य में गतिशीलता ही उचित उपाय है।आप ईश्वर की परीक्षा लेते हो। परीक्षा लेना अज्ञानता का अंश है। आप केवल उसी की परीक्षा लेते हैं, जिसके प्रति निश्चित नहीं होते। यदि ईश्वर आपकी परीक्षा लेंगे, तो इसका अर्थ होगा कि वह आपको अच्छी तरह जानते नहीं। आप कैसे सोच सकते हो कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं? ईश्वर आपकी परीक्षा नहीं लेते, क्योंकि वह आपको पूर्ण रूप से जानते हैं- आपका भूत, वर्तमान व भविष्य। वह आपके सामर्थ्य और कमजोरियों को जानते हैं और वही आपको बल देते हैं।

शख्सियत | अटल बिहारी वाजपेयी

राष्ट्रवाद और काव्य की अनूठी छवि

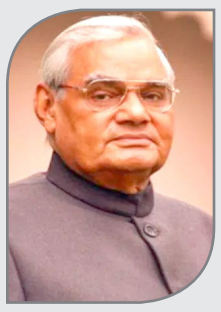

अटल बिहारी वाजपेयी (25 दिसंबर 1924 – 16 अगस्त 2018) भारतीय राजनीति और साहित्य के एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे। वे भारत के दसवें प्रधानमंत्री रहे और तीन बार इस पद पर बैठे। उनका पहला कार्यकाल केवल 13 दिन (16 मई 1996 – 1 जून 1996) का था, जबकि उनका दूसरा और तीसरा कार्यकाल क्रमशः 19 मार्च 1998 – 13 अक्टूबर 1999 और 13 अक्टूबर 1999 – 22 मई 2004 तक चला। वे भारतीय जनता पार्टी (**BJP**) के संस्थापकों में से एक थे और इसके पहले अध्यक्ष भी बने।

अटल जी का जन्म ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर में अध्यापक और हिंदी व ब्रज भाषा के कवि थे। परिवारिक माहौल और वंशानुगत कवि प्रतिभा ने उन्हें छोटी उम्र से ही साहित्यिक और राष्ट्रीय चेतना की ओर अग्रसर किया। उन्होंने लखनऊ के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एम.ए. किया और एलएलबी की पढ़ाई भी शुरू की, लेकिन पूरी निष्ठा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और जनसंघ के कार्य में जुट गए। उन्होंने पाञ्चजन्य, राष्ट्रधर्म, वीर अर्जुन और दैनिक स्वदेश जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। वाजपेयी राजनीति में अत्यंत अनुभवशील और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने 1957 में बलरामपुर से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता और 1977 तक जनता पार्टी में संसद के प्रमुख सदस्य रहे। 1980 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई और पार्टी को नई दिशा दी। अटल जी न केवल एक कुशल राजनेता थे, बल्कि भारतीय राजनीति के सजग प्रहरी भी थे। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने देश की राजनीति में स्थायित्व और विकास के नए आयाम स्थापित किए। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हुईं। 1998 में पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण कर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति स्थापित की। उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधार की दिशा में पहल की और दिल्ली-लाहौर बस सेवा की शुरुआत की। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीय सेना का साहसिक नेतृत्व किया और सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। उनके शासनकाल में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जैसी सड़क निर्माण योजनाओं से भारत के चारों कोनों को जोड़ने का काम हुआ। उन्होंने कोकण रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, नई टेलीकॉम नीति, ग्रामीण रोजगार योजनाओं और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएँ लागू की। अटल जी जीवन भर अविवाहित रहे और उन्हें भीष्मपितामह की उपाधि दी गई। वे एक महान कवि और वक्ता भी थे। उनके काव्य संग्रह "मेरी इक्यावन कविताएँ" और "कैदी कविराय की कुण्डलियाँ" ने उनके साहित्यिक व्यक्तित्व को उजागर किया।

जीवन ऊर्जा

जेम्स प्रेस्कॉट जूल : जन्म - 24 दिसंबर 1818 | देहावसान

जेम्स प्रेस्कॉट जूल एफआरएस एफआरएसई एक अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उनका जन्म 24 दिसंबर 1818 को लंकाशायर, इंग्लैंड में हुआ था। जूल ने ऊष्मा की प्रकृति का अध्ययन किया और यांत्रिक कार्यों से इसके संबंध की खोज की। इससे ऊर्जा संरक्षण का नियम सामने आया, जिसके परिणामस्वरूप ऊष्मागतिकी का पहला नियम विकसित हुआ।

शक्तिशाली विचार सिर्फ आपकी जेब में हैं

ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत मेरे लिए हमेशा एक अत्यधिक सौंदर्यपूर्ण और सुंदर सिद्धांत रहा है। मैं इसे डिस्पोजेबल कार्य के लिए एक लाभप्रद व्यवस्था के रूप में मानता हूं कि जब समान मात्रा में कार्य का उत्पादन किया जाता है तो तेल की खपत की जा सकती है। एक इंजीनियर को थर्मो-डायनामिक्स को समझना चाहिए। ऊष्मा की वह मात्रा जो एक पाउंड पानी के तापमान को एक डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने में सक्षम है, ऊष्मा की एक इकाई कहलाती है। कहीं भी, कभी भी अपने दिमाग को सशक्त बनाएं। किसी वैज्ञानिक अनुशासन की जीवन शक्ति उसमें नये विचारों वाले युवाओं की उपस्थिति पर निर्भर करती है। मैंने इस विरोधाभास, या पवित्र रहस्य को भौतिकी के कई छात्रों और कुछ हद तक सार्वजनिक रूप से बताया है। प्रतिक्रियाएं विविध रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि टकराव नैतिक

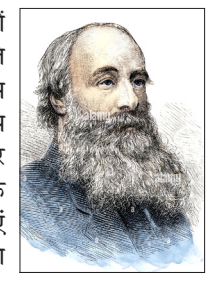

सिद्धांत की सच्चाई की पुष्टि करता है - दूसरों ने इसे शब्दों में विरोधाभास के रूप में निंदा की है। कुछ भी प्रकृति को भ्रम में नहीं डालता, कुछ भी मनुष्य और मनुष्य के बीच संबंधों को नष्ट नहीं करता है, और मानवीय कार्यों की शालीनता को भ्रष्ट करता है, व्यापारियों की आपसी ईर्ष्या से अधिक। गुणवत्ता, नैतिक श्रेष्ठता - नई साहित्यिक प्रथा की साज-सज्जा ।ब्रह्माण्ड शक्ति से परिपूर्ण है. यह संबंधों की एक प्रणाली की स्थापना है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं - ठोस, तरल और गैस - न केवल आकार में भिन्न होती हैं, बल्कि खुद को कई तरीकों से प्रकट करती हैं। शक्तिशाली विचार सिर्फ आपकी जेब में हैं। मेरे गहरे हृदय की ऊर्जा विज्ञान में नए आंदोलन को, या यूं कहें कि नई पद्धति को, धारणा को दी जाती है।

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्यप्रदेश

धन का घमंड और ऐश्वर्य असली मूल्य नहीं रखते

एक समय की बात है राजा कुबेर, जिन्हें शास्त्रों में धन के देवता और धन का राजा कहा जाता है। अपनी अपार संपत्ति और ऐश्वर्य से बहुत खुश और गर्वित थे। वह पूरी दुनिया के सबसे समृद्ध देवता थे। उनका अहंकार बढ़ने लगा था और वह अपने धन का अतिरेक रूप से प्रदर्शन करने का सोचने लगे। एक दिन कुबेर ने न केवल देवताओं, बल्कि भगवान शिव को भी अपने घर भोजन पर बुलाने का विचार किया। कुबेर का घमंड इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने सोचा कि मैं पूरे ब्रह्मांड का राजा हूं। मेरी संपत्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मैं भगवान शिव को भी अपने घर भोजन पर बुलाता हूं तो वह भी मेरे धन और ऐश्वर्य से चकित हो जाएंगे। वह भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। भगवान शिव ने कुबेर के घमंड को समझा और सोचा कि अब उन्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती से इस बारे में चर्चा की और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। भगवान शिव ने कुबेर से कहा-मैं कैलाश छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन आप मेरे स्थान पर गणेश जी को भेज सकते हैं। वह बहुत विनम्र हैं, और जल्दी तृप्त नहीं होते। इसलिये आप उन्हें भोजन कराकर देख सकते हैं। कुबेर ने अहंकार से भरकर भगवान शिव के आदेश को स्वीकार कर लिया और गणेश जी को भोजन पर बुलाने के लिए अपने महल में भेज दिया। गणेश जी भगवान शिव के आदेश से कुबेर के महल में पहुंचे। उनका रूप अत्यंत आकर्षक था और उनके साथ भगवान शिव की कृपा का आशीर्वाद था कुबेर ने उन्हें ताजे और स्वादिष्ट भोजन का न्योता दिया। अपने ऐश्वर्य और धन का पूरा प्रदर्शन करते हुए कुबेर ने स्वर्ण से बने बर्तनों में मोती माणिक्य और बहुमूल्य रत्नों से सजे पकवान गणेश जी के सामने रखे। लेकिन गणेश जी ने बड़े ही शांत और सहज रूप से भोजन करना शुरू किया। उन्होंने जो भी भोजन लिया वह खत्म होता चला गया। लेकिन गणेश जी का पेट कभी नहीं भरा। समय बीतता गया और कुबेर के भोजन की विशाल सामग्री धीरे-धीरे समाप्त होती चली गई। कुबेर का घबराहट और चिंता बढ़ने लगी वह सोचने लगे कि यह क्या हो रहा है इतने सारे स्वादिष्ट पकवानों के बाद भी गणेश जी का पेट नहीं भर रहा है।

कुबेर की हालत खराब होने लगी और वह अपने हाथों में वह अपार धन जो उन्होंने कुबेर के महल में रखा था। वह अब उनके सामने बेमानी सा लगने लगा। बिना वक्त गंवाए वह भगवान शिव के पास पहुंचे और पूरी घटना का विस्तार से बयान किया। कुछ ही देर में गणेश जी भी भगवान शिव के पास पहुंचे भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पार्वती से कहा- मां आप कुछ खाना ले आइए पार्वती जी ने तुरंत अपनी रसोई से घर का बना भोजन भगवान गणेश के सामने रखा। जैसे ही गणेश जी ने मां पार्वती के हाथों का भोजन लियाउनका पेट तुरंत भर गया यह दृश्य देखकर कुबेर की आँखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ गए कि धन का घमंड और ऐश्वर्य असली मूल्य नहीं रखते, बल्कि विनम्रता और सच्चाई का सच्चा महत्व होता है। भगवान गणेश का यह चमत्कार और भोलेनाथ का सटीक निर्णय कुबेर को बड़ा पाठ पढ़ा गया। कुबेर ने भगवान शिव से माफी मांगी और उनसे यह वचन लिया कि वह अब घमंड और अहंकार से बचेंगे। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि वह अब अपने धन का उपयोग केवल भलाई के कामों में करेंगे और किसी को भी घमंड करने का मौका नहीं देंगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि धन और ऐश्वर्य कभी किसी के सच्चे मूल्य का पैमाना नहीं होते।

पंडित कैलाशचंद्र शर्मा
वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक।
मो. नं. 9425980556

अपने विचार

इंडिगो के मालिक को भारत और पाकिस्तान दोनों के मुस्लिम समर्थकों की बात सुननी चाहिए और मैं चुप नहीं रहने वाली हूं। जब भी इंडिगो के उम्माह कर्मचारी अपनी जिहादी मानसिकता का प्रदर्शन करेंगे, तब मैं उनके हिजाब उतार दूंगी। यह मेरी चुनौती है।

-नाजिया इलाही खान
नेता, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा

मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जो कि राजनीति करते हुए लोगों को गुमराह करें। जहां तक केंद्र सरकार अच्छा काम करती है, वहां तक मैं उसकी सराहना करता हूं और जहां कमी है, वहां खुलकर आलोचना भी करता हूं।

-उमर अब्दुल्ला
सीएम, जम्मू और कश्मीर

बीजेपी भारत के संस्थागत ढांचे को अपनी निजी संपत्ति की तरह देखती है और इसका उपयोग राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए करती है। भारत में ऐसा माहौल बन गया है, जहां संस्थाएं वह भूमिका नहीं निभा पा रही हैं, जिसके लिए उन्हें बनाया गया था।

-राहुल गांधी
नेता, विपक्ष

प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ और देखो कि वो इंदिरा गांधी की तरह कैसे जवाब देती हैं। उनके नाम के पीछे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया था कि आज भी उन घावों का दर्द बाकी है।

-इमरान मसूद
नेता, कांग्रेस

अपने विचार

डीबीडी कार्यालय
ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001
indiagroundreport@gmail.com
भेज सकते हैं।

यह अखबार "माध्यम कार्पोरेट सर्विसेज लि. " के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक अरुण लाल द्वारा ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 से प्रकाशित एवं सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन.के.इंडस्ट्रियल इस्टेट, इनसाइड प्रवासी इंडिस्ट्रयल इस्टेट गेट नं. 2, गोरेगांव पू., मुंबई-63 से मुद्रित. फोन नं. 022-66555719 ईमेल : indiagroundreport@gmail.com **कार्यकारी संपादक :** अमित बृज (पी.आर.बी. अधिनियम के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए ज्मिेदार).

ब्रीफ न्यूज़

मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कक्ष का आयुक्त ने की समीक्षा

ठाणे। मनपा आम चुनाव 2025-26 को पारदर्शी और सुचारू तरीके से संचालित करने के लिए प्रशासन ने पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार कर लिया है। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, मनपा मुख्यालय की पहली मंजिल पर स्वर्गीय नरेंद्र बल्लाल हॉल में 'मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष' स्थापित किया गया है। आज इस कक्ष का निरीक्षण मनपा के चुनाव अधिकारी एवं आयुक्त सौरभ राव ने किया। इस मौके पर अतिरिक्त आयुक्त 2 प्रशांत रोडे, उपायुक्त जी.जी. गोदापुरे, उपायुक्त और चुनाव अधिकारी उमेश बिरारी तथा नोडल अधिकारी मिताली संचेती भी मौजूद थे। इस कक्ष के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए प्रस्तावित विज्ञापनों का प्री-सर्टिफिकेशन किया जाएगा और मीडिया को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।आयुक्त सौरभ राव ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी यूनिट्स से अपील की कि वे आचार संहिता का पालन करें और मीडिया सभी के लिए समान न्याय के सिद्धांत के अनुसार ऑब्जेक्टिव न्यूज़ प्रकाशित करे। उन्होंने वोटरों से भी आग्रह किया कि वे मीडिया के माध्यम से सही जानकारी लेकर सूचित तरीके से वोट दें।

अब घर के लिए मिलेगा आसान लोन, कंसल्टिंग कंपनी की नियुक्ति

मुंबईः म्हाडा के कोंकण बोर्ड ने बिके हुए लेकिन खाली पड़े घरों की बिक्री बढ़ाने के लिए नए कदम उठाए हैं। बोर्ड ने अब फैसला किया है कि एप्लिकेंट्स को बैंक के चक्कर लगाए बिना आसान होम लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने एक कंपनी को होम लोन कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त किया है। कोंकण बोर्ड ने विरार-बोलिंज में 10 हजार से ज़्यादा घरों की योजना लागू की है। वहीं खोनी, भंडारली, गोठेघर और शिरधों में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत घर बनाए जा रहे हैं। ये कदम खाली घरों को बेचने और आम लोगों को किफायती घर उपलब्ध कराने की दिशा में उठाए गए हैं। बोर्ड ने अगले छह महीनों में सभी खाली घरों को बेचने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए होम लोन एडवाइजरी कंपनी को नियुक्त किया गया है। नवंबर के आखिरी हफ्ते से कंपनी ने 36 से ज़्यादा बैंकों के साथ मिलकर एप्लिकेंट्स को 7.35 प्रतिशत के ब्याज दर पर होम लोन देना शुरू कर दिया है। PMAY स्कीम के तहत 25 लाख रुपये तक के घरों के लिए 4 प्रतिशत की दर से लोन भी उपलब्ध है। महंगे घर, प्रोजेक्ट में आवश्यक सुविधाओं की कमी और सही लोकेशन न होने के कारण लोगों ने इन घरों में रुचि नहीं दिखाई।

वर्ली में 2500 परिवारों ने वोटिंग का किया बॉयकॉट

'स्लम अथॉरिटी' के डेवलपर्स बदलने के फैसले से लोग नाराज़

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई के वर्ली इलाके में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA/झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) के एक फैसले के खिलाफ करीब 2500 परिवारों ने नगर निगम चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया है। आदर्श नगर सागर दर्शन और चैतन्य साईं जनता कॉलोनी स्लम पुनर्वसन योजना के तहत डेवलपर बदलने की प्रक्रिया शुरू किए जाने से स्थानीय लोग नाराज़ हैं और इसे उनके साथ अन्याय बता रहे हैं।

डेवलपर बदलने के फैसले से भड़के निवासी

स्लम अथॉरिटी ने दोनों परियोजनाओं में धारा 13(2) के तहत डेवलपर बदलने की प्रक्रिया शुरू की है। निवासियों का आरोप है कि जब वर्षों से रुका हुआ पुनर्वसन कार्य अब गति पकड़ चुका है, तब अचानक डेवलपर बदलने का कदम उठाकर अनावश्यक अड़चनें पैदा की जा रही हैं। इसी के विरोध में इन दोनों योजनाओं से जुड़े परिवारों ने चुनावी बहिष्कार का फैसला लिया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस और आंदोलन की चेतावनी

रविवार को सागर दर्शन और चैतन्य साईं जनता कॉलोनी के निवासियों ने वर्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्लम अथॉरिटी पर पुनर्वसन प्रक्रिया में बेवजह बाधा डालने का आरोप लगाया। सागर दर्शन हाउसिंग सोसाइटी के सचिव शेखर पलव ने चेतावनी दी कि यदि 13(2) के तहत डेवलपर बदलने की प्रक्रिया वापस नहीं ली गई, तो 2500 से अधिक परिवार न केवल वोटिंग का बहिष्कार करेंगे बल्कि आगे चलकर सार्वजनिक आंदोलन भी करेंगे। वहीं, स्लम अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि परियोजनाएं लंबे समय से रुकी हुई थीं, इसलिए नियमों के तहत 13(2) नोटिस जारी कर डेवलपर बदलने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

चैतन्य साईं जनता कॉलोनी में भी असंतोष

चैतन्य साईं जनता कॉलोनी का पुनर्वसन तकनीकी कारणों से लंबे समय तक रुका रहा, लेकिन अब जब काम आगे बढ़ने लगा है, वहां भी डेवलपर बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों की नाराज़गी इस बात को लेकर है कि इस परियोजना से जुड़ा विवाद अभी अदालत में लंबित है, इसके बावजूद स्लम अथॉरिटी ने डेवलपर बदलने का कदम उठाया।

सागर दर्शन प्रोजेक्ट का 30 साल का इतिहास

आदर्श नगर सागर दर्शन में 250 झोपड़ियों का पुनर्वसन वर्ष 1996 में शुरू हुआ था। पहले नियुक्त डेवलपर ने 1996 से 2007 तक कोई काम नहीं किया, जबकि दूसरे डेवलपर ने भी 2007 से 2020 तक परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया। अंततः 2022 में तीसरे डेवलपर को नियुक्त किया गया, जिसने सभी जरूरी अनुमतियां लेकर काम शुरू किया और एक वर्ष के भीतर नींव का काम भी पूरा कर दिया। इसके बावजूद स्लम अथॉरिटी ने यह कहते हुए 13(2) की कार्रवाई शुरू कर दी कि परियोजना लंबे समय से लंबित है, जिस पर निवासियों ने कड़ा सवाल उठाया है।

मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति गठित

डीबीडी संवाददाता | भिवंडी

भिवंडी नगर निगम के आगामी आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर अनमोल सागर के नेतृत्व में मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। इस समिति में पुलिस उपायुक्त शशिकांत बोराटे, निर्वाचन विभाग के उपायुक्त विक्रम दराडे और रिटर्निंग ऑफिसर सदस्य हैं, जबकि नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी श्रीकांत परदेशी को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रचार के दौरान अनुचित गतिविधियों और सशुल्क खबरों पर रोक लगाना है।

पेड खबरों पर नजर

चुनाव प्रक्रिया के दौरान मीडिया पर नजर रखने के लिए नगर निगम मुख्यालय की दूसरी मंजिल पर विशेष मीडिया निगरानी कक्ष स्थापित किया गया है। यहां अतिरिक्त अधिकारी और कर्मचारी ऑडियो-विजुअल मीडिया में प्रकाशित व प्रसारित होने वाली खबरों की निगरानी करेंगे। वहीं पेड खबरों पर नजर रखने की जिम्मेदारी आचार संहिता टीम के प्रमुख अतिरिक्त आयुक्त विट्ठल डाके को सौंपी गई है।

विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणीकरण अनिवार्य

चुनाव अवधि के दौरान यदि कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार टीवी, सैटेलाइट चैनल, केबल नेटवर्क, यूट्यूब, रेडियो, एफएम चैनल, सिनेमा हॉल, ई-अखबार, सोशल मीडिया, वेबसाइट, बल्क या वॉइस एसएमएस जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञापन प्रसारित या प्रकाशित करना चाहता है, तो उसे पहले समिति से पूर्व-प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा। नगर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समिति की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के विज्ञापन का प्रसारण या प्रकाशन नहीं किया जा सकेगा।

कांदिवली–बोरीवली छठी लाइन कार्य के लिए 30 दिन का मेजर ब्लॉक

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली–बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए 30 दिनों का मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक 20/21 दिसंबर 2025 की रात से शुरू होकर 18 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने से जुड़े आवश्यक तकनीकी कार्य किए जाएंगे।

परिशिष्टों में दी गई प्रभावित ट्रेनों की सूची

रेलवे प्रशासन के अनुसार, परिशिष्ट–I में 26/27 दिसंबर 2025 को ब्लॉक के दौरान गोरेगांव तक चलाकर वहीं से लौटाई जाने वाली ट्रेनों की जानकारी दी गई है। परिशिष्ट–II में 26/27 दिसंबर 2025 को निरस्त की जाने वाली ट्रेनों की सूची है। परिशिष्ट–III में 27 दिसंबर 2025 को रद्द की जाने वाली ट्रेनों का विवरण शामिल है।

उपनगरीय सेवाओं पर पड़ेगा असर

इस ब्लॉक के चलते कुछ लोकल ट्रेन सेवाएं रद्द रहेंगी, जबकि कुछ बोरीवली और अंधेरी से चलने वाली लोकल ट्रेनों को गोरेगांव तक ही सीमित किया जाएगा और वहीं से वापस चलाया जाएगा। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए प्रभावित ट्रेनों का विस्तृत विवरण परिशिष्टों में दिया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बोरीवली स्टेशन पर अप और डाउन स्लो लाइनों में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) पैनल के कमीशनिंग कार्य हेतु 26 और 27 दिसंबर 2025 को रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक मेजर नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इसके अलावा, 26 दिसंबर की रात 11 बजे से 27 और 28 दिसंबर की मध्यरात्रि तक कांदिवली–दहिसर के बीच डाउन फास्ट लाइन पर गति प्रतिबंध लागू रहेगा।

भक्तिमय वातावरण में वार्षिक महोत्सव हुआ संपन्न

डीबीडी संवाददाता | भाईंदर

श्री सालासर हनुमान सेवा मंडल, मुंबई (रजि.) का 29वां वार्षिक महोत्सव भाईंदर (प.) स्थित बालाजी मैदान में भक्तिमय वातावरण में हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। प्रातः श्रीराम के पावन नाम के उच्चारण के साथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसके बाद देर रात तक भजनों की मधुर प्रस्तुतियों ने पूरे परिसर को राममय बना दिया। खलिलाबाद के प्रसिद्ध भजन गायक रोमी सरदार ने अपनी सुमधुर भजन गायन से श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया।

भव्य झांकियां और छप्पन भोग

महोत्सव के दौरान श्री सालासर बालाजी, श्री श्याम जी एवं माता रानी सती की मनमोहक झांकियों और भव्य श्रृंगार ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रभु भक्तों के बीच विराजमान हों। भक्ति और विश्वास की अखंड ज्योत प्रज्वलित कर प्रभु को छप्पन भोग अर्पित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया।

समाजसेवा में भी अग्रणी मंडल

गौरतलब है कि श्री सालासर हनुमान सेवा मंडल की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। मंडल समाजसेवा और धार्मिक कार्यों में लगातार सक्रिय भूमिका निभाता आ रहा है। हर वर्ष यह वार्षिक महोत्सव भक्ति और श्रद्धा के साथ आयोजित किया जाता है। धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ मंडल सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करता है, जिसके तहत आदिवासी क्षेत्रों में अनाज, कपड़े और कंबलों का वितरण नियमित रूप से किया जाता है।

तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में संशोधन

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

रेलवे बोर्ड के निर्देशों के तहत पश्चिम रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में अहम संशोधन करने जा रही है। अब तत्काल टिकट केवल सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए वन टाइम पासवर्ड (OTP) के प्रमाणीकरण के बाद ही जारी किए जाएंगे। टिकट बुकिंग के समय यात्री द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर यह ओटीपी भेजा जाएगा और सफल सत्यापन के बाद ही टिकट जारी होगा।

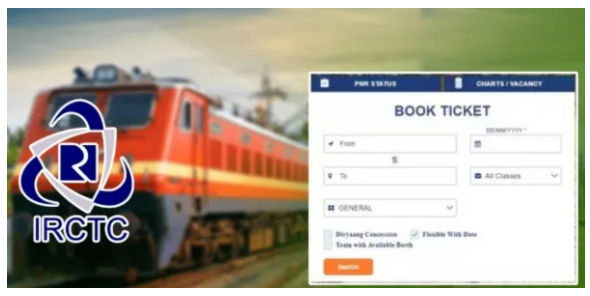

चार और ट्रेनों में लागू होगी OTP व्यवस्था

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ओटीपी आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली पहले ही पश्चिम रेलवे से चलने वाली 21 ट्रेनों में लागू की जा चुकी है। अब 24 दिसंबर 2025 से यह व्यवस्था चार और ट्रेनों—14702 बांद्रा टर्मिनस–श्रीगंगानगर एक्सप्रेस, 19037 बांद्रा टर्मिनस–बरौनी एक्सप्रेस, 19483 अहमदाबाद–सहरसा एक्सप्रेस और 22956 भुज–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस—में भी लागू की जाएगी।

पारदर्शिता और वास्तविक यात्रियों को लाभ

यह नई ओटीपी आधारित प्रणाली कम्प्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों, अधिकृत एजेंटों, आईआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाने वाली तत्काल बुकिंग पर लागू होगी। इसका मुख्य उद्देश्य तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और वास्तविक यात्रियों को टिकट प्राप्त करने में बेहतर सुविधा प्रदान करना है।

अटल जयंती पर 'सुशासन सप्ताह' की शुरुआत

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में 'सुशासन सप्ताह' का आयोजन किया जा रहा है। इस सप्ताह का उद्देश्य आम नागरिकों को यह समझाना है कि प्रशासन किस प्रकार जनता के हित में कार्य करता है। इसी क्रम में ठाणे में आयोजित एक वर्कशॉप में जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान कर उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए।

विशेष कार्यशाला का आयोजन

प्रशासन को सर्विस सुविधाएं देकर जनता की समस्याओं को हल करना चाहिए: जिलाधिकारी

पारदर्शिता, गति और तकनीक पर जोर

जिलाधिकारी डॉ. पांचाल की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, तेजी और आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए विशेष शिविर लगाए जाएं, जन शिकायतों का त्वरित निवारण हो, ऑनलाइन सेवाएं बिना देरी के उपलब्ध कराई जाएं और प्रत्येक कार्य का रिकॉर्ड अद्यतन रखा जाए।

'एडमिनिस्ट्रेशन गांव का गांव है' की सोच

डॉ. पांचाल ने कहा कि हर अधिकारी और कर्मचारी को नागरिकों की व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं को संवेदनशीलता और सकारात्मक रवैये के साथ सुनना चाहिए। "एडमिनिस्ट्रेशन गांव का गांव है" यह अवधारणा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य करने का अवसर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सप्ताह केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित किया गया है।

गुड गवर्नेंस के तीन स्तंभ

जिलाधिकारी ने बताया कि सुशासन के तीन प्रमुख आधार हैं—सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी, शिकायत निवारण और पारदर्शिता। समस्याओं का समाधान कानून और व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ-साथ मानवीय संवेदना के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल टूल्स के उपयोग से प्रशासनिक कार्यों में मानवीय हस्तक्षेप कम होता है और पारदर्शिता बढ़ती है।

ई-गवर्नेंस से बेहतर सेवा का लक्ष्य

डॉ. पांचाल ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ ई-गवर्नेंस का प्रभावी उपयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को कार्यालय आए बिना सेवाएं मिलना ही सुशासन की वास्तविक सफलता है। साथ ही, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और शिकायतों का समयबद्ध निपटारा ही प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इस वर्कशॉप में अतिरिक्त जिलाधिकारी हरिश्चंद्र पाटिल, निवासी उप जिलाधिकारी डॉ. संदीप माने, उप जिला चुनाव अधिकारी वैशाली माने, जिला नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी, जिला सूचना अधिकारी मनोज सुमन शिवाजी सानप सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

12 राशिफल में देखें अपना दिन

मेष संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी। यात्रा व निवेश मनोनुकूल रहेंगे। कानूनी मामलों में लापरवाही न करें। सम्मान व कीर्ति में वृद्धि होगी। व्यापार में नए प्रस्तावों से लाभ मिलने के योग हैं।

वृष विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। प्रसन्नता रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारी का पूर्ण ध्यान रखें। रचनात्मक कार्यों का प्रतिफल प्राप्त होगा। व्यापार में उन्नति होगी।

मिथुन बुरी खबर मिल सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दौड़धूप अधिक होगी। दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं। मकान व जमीन संबंधी कार्य बनेंगे। संतान पर अनावश्यक रोक न लगाएँ। धन लाभ होने की भी संभावना है। सामाजिक कार्यों में सीमित रहें।

कर्क मेहनत का फल मिलेगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। निवेश, यात्रा व नौकरी लाभ देंगे। अपने प्रयासों से उन्नति पथ प्रशस्त करेंगे। इच्छित काम पूर्ण हो सकेंगे। स्वास्थ्य की समस्या सुलझेगी। नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी।

सिंह अतिथियों का आगमन होगा। उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी। प्रसन्नता रहेगी। स्वाभिमान रहेगा। प्रमाद न करें। बुद्धि चातुर्य से कठिन कार्य भी आसानी से बनेंगे। वैवाहिक अड़चनें समाप्त होंगी।

कन्या यात्रा, निवेश व नौकरी मनोनुकूल रहेंगे। भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। भौतिक विकास के कार्यों को बल मिलेगा। भागीदारी के प्रस्ताव आएँगे। दिनचर्या नियमित रहेगी। रिश्तेदारों से भेंट हो सकेगी। दूसरों की आलोचना, निंदा से दूर रहें।

तुला क्रोध पर नियंत्रण रखें। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। दूसरों पर अतिविश्वास न करें। नई योजनाओं का सूत्रपात होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। व्यावसायिक समस्याओं का हल आपके माध्यम से हो सकेगा।

वृश्चिक लेन-देन में सावधानी रखें। पुरानी लेनदारी वसूल होगी। यात्रा सफल रहेगी। प्रसन्नता रहेगी। प्रमाद न करें। नवीन वस्त्राभूषण की प्राप्ति होगी। व्यवहार-कुशलता से समस्या का समाधान संभव है।

धनु योजना फलीभूत होगी। धन प्राप्ति सुगम होगी। प्रसन्नता रहेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। अधूरे पड़े कार्य पूरे होंगे। जीवनसाथी से संबंधों में मधुरता आएगी। प्रयास व सहयोग से अनुकूलता आएगी। पिता से व्यापार के विषय में मतभेद हो सकते हैं।

मकर धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। सत्संग का लाभ मिलेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रसन्नता रहेगी। प्रमाद न करें। नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। सुखद यात्रा के योग हैं। रचनात्मक काम होंगे। आलस्य को त्यागकर कार्यों को समय पर करने से सफलता प्राप्त हो सकती है।

कुंभ वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। सोच-समझकर व्यय करें। व्यापार लाभप्रद रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। विवाद समाप्त होने से शांति एवं सुख बढ़ेगा।

मीन प्रेम-प्रसंग में सफलता मिलेगी। कानूनी बाधा दूर होगी। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रसन्नता रहेगी। परोपकारी स्वभाव होने से दूसरों की मदद कर पाएँगे। काम के प्रति लापरवाही न करें। प्रयत्न एवं दूरदर्शिता से सहयोग व समर्थन मिलेगा। लाभ होगा।

हनुमानजी की कृपा से आर्थिक तंगी दूर करने की चमत्कारी साधना

प्रियंका जैन
9769994439

प्राचीन काल से ही भक्तों के लिए हनुमानजी विशिष्ट स्थान रखते आए हैं। वे केवल शक्ति और साहस के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि कलियुग में हर भक्त की मनोकामना पूरी करने वाले शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीरामचरितमानस में बताया गया है कि माता सीता ने पवनपुत्र हनुमान को अमरता का वरदान दिया, जिससे उन्हें अष्टचिरंजीवी में शामिल किया गया। यही कारण है कि हनुमानजी का आशीर्वाद भक्तों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाता है।

आज के समय में जब लोगों को आर्थिक संकट और जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब हनुमानजी की कृपा ही सबसे प्रभावकारी उपाय बन जाती है। उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से किए गए साधन से जीवन में धन-संपत्ति, सुख-शांति और समृद्धि का प्रवेश होता है। इस विश्वास के साथ कई पीढ़ियों से हनुमानजी के भक्त नियमित रूप से उपाय करते आए हैं।

सबसे प्रभावशाली उपायों में से एक उपाय पीपल के पत्तों से की जाने वाली साधना है। इस उपाय में मंगलवार और शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पीपल के 11 पूर्ण पत्ते तोड़े जाते हैं। यह पत्ते न टूटे और न खंडित होने चाहिए। प्रत्येक पत्ते पर स्वच्छ जल में कुमकुम, अष्टगंध या चंदन मिलाकर श्रीराम का नाम लिखा जाता है। नाम लिखते समय हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाता है। जब सभी पत्तों पर श्रीराम नाम लिख दिया जाता है, तो इन पत्तों की माला बनाकर किसी भी हनुमानजी के मंदिर में अर्पित की जाती है। इस साधना को नियमित रूप से करने से न केवल आर्थिक तंगी दूर होती है, बल्कि जीवन में बाधाएं भी समाप्त होने लगती हैं। इतना ही नहीं, हनुमानजी की कृपा प्राप्त करने के लिए नारियल अर्पित करना भी अत्यंत प्रभावकारी उपाय माना गया है। भक्त मंदिर जाकर अपने साथ नारियल लाते हैं, उसे अपने सिर पर सात बार मारते हैं और फिर हनुमानजी को अर्पित कर देते हैं। इस सरल परंतु चमत्कारी उपाय से घर-परिवार की सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं और व्यक्ति को जीवन में संतोष और समृद्धि प्राप्त होती है। शनिवार का दिन हनुमानजी की विशेष कृपा का प्रतीक है। इस दिन यदि किसी हनुमान मंदिर में नारियल पर स्वस्तिक बनाकर अर्पित किया जाए और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, तो उपाय और भी प्रभावकारी बन जाता है। इसके अलावा हनुमानजी को सिंदूर और तेल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। जैसे विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, वैसे ही हनुमानजी अपने स्वामी श्रीराम के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगाते हैं। शनिवार को हनुमानजी को सिंदूर अर्पित करने वाले भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं।

भक्ति और श्रद्धा के अनुसार हनुमानजी की प्रतिमा पर चोला चढ़वाना भी अत्यंत प्रभावकारी उपाय है। इसे नियमित रूप से करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। इसके साथ ही शनिवार की रात को हनुमानजी के सामने चौमुखा दीपक जलाना भी एक छोटा परन्तु चमत्कारी उपाय है। इसे नियमित रूप से करने से घर-परिवार की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हनुमानजी की कृपा पाने का एक अन्य उपाय पीपल पेड़ से जुड़ा हुआ है। किसी पीपल पेड़ को जल चढ़ाएं, उसके चारों ओर सात परिक्रमा करें और पीपल के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से न केवल आर्थिक तंगी दूर होती है, बल्कि जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता भी आती है।

न्यूज़ ब्रीफ

केजीएमयू में लव जिहाद मामला जूनियर डॉक्टर निलंबित

लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू), लखनऊ में सामने आए लव जिहाद के एक गंभीर मामले में आरोपी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता से फोन पर बात कर उसे न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया है। जानकारी के अनुसार, केजीएमयू के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. रमीज उद्दीन नायक पर आरोप है कि उसने अपनी शादी की सच्चाई छिपाकर एक हिंदू महिला डॉक्टर से संबंध बनाए और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। शिकायत मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंगलवार को उसे निलंबित कर दिया। केजीएमयू की कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद की अनुमति से डीन एकेडमिक्स प्रो. वीरेंद्र आतम ने निलंबन का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि यह कार्रवाई यौन उत्पीड़न की शिकायत के आधार पर की गई है, जिस पर विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति ने संज्ञान लिया है। निलंबन अवधि के दौरान आरोपी डॉक्टर केजीएमयू मुख्यालय में उपस्थित रहेगा, लेकिन कोई भी आधिकारिक काम नहीं करेगा। बिना अनुमति परिसर में प्रवेश भी नहीं कर सकेगा और केवल जांच प्रक्रिया में ही शामिल होगा। यह मामला बीते शनिवार को उस समय चर्चा में आया, जब पीड़िता महिला डॉक्टर ने उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में उसे केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पीड़िता के परिजनों ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल और राज्य महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है।

MNNIT: पूर्व प्रवक्ता की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट को आपत्ति

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) के पूर्व प्रवक्ता राजेश सिंह को सेवा से हटाने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि जिस आरोप के आधार पर उन्हें बर्खास्त किया गया, उसके मुकाबले सजा बहुत कठोर है। कोर्ट ने संस्थान को निर्देश दिया है कि वह अपने फैसले पर दोबारा विचार करे और हल्का दंड देने की संभावना पर विचार करे। राजेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने यह आदेश दिया। मामले के अनुसार, राजेश सिंह की नियुक्ति वर्ष 1999 में एमएनएनआईटी के कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रवक्ता के पद पर हुई थी। वर्ष 2003 में विभाग की एक पूर्व छात्रा ने संस्थान के निदेशक से शिकायत की थी कि याची ने उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत में यह भी कहा गया था कि संस्थान छोड़ने के बाद भी दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध बने रहे। दोनों के बीच विवाह भी हुआ, लेकिन अलग-अलग धर्म होने के कारण याची के परिजन इस विवाह को स्वीकार नहीं कर पाए। शिकायतकर्ता ने शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस शिकायत के बाद संस्थान ने पांच सदस्यीय जांच समिति बनाई, लेकिन समिति किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। रिपोर्ट में कहा गया कि समिति यह तय करने में सक्षम नहीं है कि दुष्कर्म हुआ या नहीं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि शिकायत संस्थान छोड़ने के बाद दर्ज कराई गई थी और दोनों के बीच संबंध सहमति से थे।

कानून की सही जानकारी नहीं रखते अधिकारी: हाईकोर्ट

एजेंसी । प्रयागराज

मृतक आश्रित नियुक्ति मामले में उच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी

अदालतों पर बढ़ रहा अनावश्यक बोझ, आम आदमी झेल रहा मुकदमा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों में काम कर रहे अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि कई सरकारी अधिकारी कानून की सही जानकारी नहीं रखते, जिसके कारण बेवजह मामले अदालतों तक पहुंचते हैं। इससे न केवल अदालतों पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है, बल्कि आम लोगों को भी बिना वजह मुकदमेबाजी करनी पड़ती है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने मृतक आश्रित में नियुक्ति से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि जिम्मेदार अधिकारी कानूनी नियमों को नजरअंदाज करते हैं या तय कानून के विपरीत फैसले ले लेते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि ऐसे मामले अदालत में पहुंच जाते हैं और न्यायिक समय की बर्बादी होती है। मामले के अनुसार, याची के पिता की नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसकी मां ने विभाग से अनुरोध किया था कि बेटे के बालिग होने पर उसे मृतक आश्रित कोटे में नौकरी दी जाए। वर्ष 2007 में याची को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में कंडक्टर के पद पर नियुक्त किया गया, लेकिन यह नियुक्ति संविदा के आधार पर थी।

अशिक्षित याची को नहीं था कानून का इल्म

याची अशिक्षित था और उसे अपनी नियुक्ति की प्रकृति और उससे जुड़े कानून की जानकारी नहीं थी। कई साल नौकरी करने के बाद उसने अपनी संविदात्मक नियुक्ति को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी और कुछ पुराने फैसलों का हवाला दिया। निगम की ओर से दलील दी गई कि याची इतने वर्षों तक काम करने के बाद अब अपनी नियुक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य और उसके उपक्रमों की जिम्मेदारी है कि वे संविधान के तहत निष्पक्ष और तार्किक तरीके से काम करें, खासकर तब जब मामला ऐसे लोगों से जुड़ा हो, जिन्हें कानून की पूरी समझ नहीं होती।

जानकारी होते हुए क्यों की गई नियुक्ति ?

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सरकार को अनावश्यक मुकदमेबाजी कम करने की दिशा में काम करना चाहिए। इससे अदालतों में मामलों की संख्या घटेगी और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। अदालत ने साफ कहा कि जब विभाग को कानून की स्थिति पहले से पता थी, तो ऐसी नियुक्ति ही नहीं की जानी चाहिए थी। विभाग की गलती का नुकसान कर्मचारी को नहीं भुगतना चाहिए। हाईकोर्ट ने निगम को मामले पर दोबारा विचार करने और कानून के अनुसार जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

बिना नियुक्ति मदरसे से मिलता रहा वेतन

उच्चस्तरीय जांच शुरू, अधिकारी भी संदेह के घेरे में

एजेंसी । लखनऊ/बलरामपुर

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर स्थित मदरसा जामिया अनवारुल उलूम में बिना नियुक्ति के ही महीनों तक वेतन भुगतान किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस प्रकरण को देखते हुए उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी गई है। मामले में मदरसा प्रबंधन के साथ-साथ जिला अल्पसंख्यक अधिकारी (डीएमओ) की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। जानकारी के अनुसार, इसी मदरसा में हाल ही में फर्जी नियुक्ति के एक मामले में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अभी उस मामले में गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी कि अब एक और खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि मदरसा में एक शिक्षक का पद खाली होने के बावजूद कई महीनों से उस पद के नाम पर वेतन निकाला जा रहा था। तुलसीपुर निवासी इमरान ने इस संबंध में लिखित शिकायत की थी। शिकायत के बाद जब मदरसा के रिकॉर्ड की जांच कराई गई तो नियुक्ति से जुड़ा कोई आदेश, चयन प्रक्रिया या उपस्थिति रजिस्टर नहीं मिला। इसके बावजूद लगातार वेतन भुगतान होने की बात सामने आई, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है। मदरसा के कार्यकारी प्रधानाचार्य और कुछ शिक्षकों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जिस व्यक्ति के नाम पर वेतन निकाला गया, उसे न तो स्टाफ ने कभी देखा और न ही छात्रों ने। सभी जानते थे कि एक पद खाली है, फिर भी भुगतान कैसे और किसे हुआ, यह किसी को नहीं पता।

रजिस्ट्रार को मिली जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए मदरसा निदेशक, लखनऊ ने पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी मदरसा रजिस्ट्रार को सौंपी गई है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि जांच के दायरे में मदरसा प्रबंधन के साथ-साथ भुगतान को मंजूरी देने वाले अधिकारी भी आ सकते हैं। शिकायतकर्ता इमरान का कहना है कि मदरसों में नियुक्ति और वेतन भुगतान की प्रक्रिया में प्रबंधक, लिपिक और डीएमओ की अहम भूमिका होती है। ऐसे में यदि बिना नियुक्ति के वेतन दिया गया है तो कार्रवाई केवल मदरसा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से डीएमओ के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।

पहले भी हुआ है फर्जीवाड़ा

इस मामले पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी यशवंत मौर्य ने बताया कि जांच रिपोर्ट निदेशक को भेज दी गई है और आगे की कार्रवाई उनके निर्देश पर की जाएगी। वहीं, मदरसा निदेशक अंकित अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि इसी मदरसा में पहले भी मृतक आश्रित कोटे में शिक्षक नियुक्ति को लेकर फर्जीवाड़े का मामला सामने आ चुका है। लगातार हो रहे इन खुलासों से मदरसा शिक्षा व्यवस्था और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

कफ सिरप: इनामी सरगना समेत चार को लुकआउट नोटिस

एजेंसी । वाराणसी

कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के मामले में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 50 हजार रुपये के इनामी सरगना शुभम जायसवाल समेत चार फरार आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। यह कदम आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जिन लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, उनमें शुभम जायसवाल के अलावा आकाश पाठक, दिवेश जायसवाल और अमित जायसवाल शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि इन आरोपियों की तलाश के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) लगातार दबिश दे रही है। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी को आरोपियों के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े हुए हैं और फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये का कारोबार कर रहे थे। जांच के अनुसार, रांची की शैली ट्रेडर्स फर्म का संचालन शुभम जायसवाल करता था, जबकि डीएसए फार्मा दिवेश जायसवाल के नाम पर चल रही थी। अन्य आरोपियों में काजीपुरा खुर्द निवासी अमित जायसवाल और गोलघर क्षेत्र के सिद्ध माता लेन निवासी आकाश पाठक शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शुभम जायसवाल वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के प्रहलाद घाट कायस्थ टोला का रहने वाला है और उस पर पहले ही 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है। पूरे नेटवर्क की जांच में ड्रग विभाग से भी जानकारी ली जा रही है।

फर्जी फर्मों के सहारे की गई सप्लाई

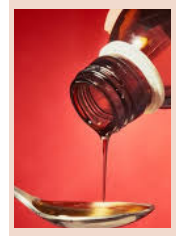

एसआईटी की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी युवकों के नाम पर फर्जी फर्में खुलवाते थे। इन फर्मों के बैंक खाते, जीएसटी नंबर और अन्य जरूरी कागजात आरोपियों के ही कब्जे में रहते थे। फर्जी ई-वे बिल बनाकर कोडीन कफ सिरप की सप्लाई की जाती थी। जिन युवकों के नाम पर फर्में खोली जाती थीं, उन्हें हर महीने 40 से 50 हजार रुपये दिए जाते थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा।

यूपी में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दे रही योगी सरकार

दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मिली मंजूरी

एजेंसी । लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवहन को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश में दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इससे ग्रीन हाइड्रोजन पर शोध, नई तकनीक के विकास और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी निर्णय के अनुसार, पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी कानपुर द्वारा हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय (एचबीटीयू), कानपुर के सहयोग से बनाया जाएगा। दूसरा सेंटर आईआईटी-बीएचयू द्वारा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी), गोरखपुर के साथ मिलकर स्थापित किया जाएगा। दोनों सेंटर अपने-अपने साझेदार संस्थानों के परिसरों से संचालित होंगे। यूपी नेडा के प्रबंध निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि ये सेंटर 'हब एंड स्पोक मॉडल' पर काम करेंगे। इसका मतलब है कि इनसे प्रदेश के अन्य इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थान भी जुड़ेंगे। यहां बायोमास और इलेक्ट्रोलाइजर आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पर शोध और तकनीकी विकास किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024 के तहत इन सेंटरों में इन्क्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। इसके जरिए हर साल 10 नए स्टार्टअप्स को सहयोग मिलेगा और पांच साल में कम से कम 50 स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में मदद दी जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से पांच वर्षों तक हर साल 25 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलीटेक्निक संस्थानों के लिए नए पाठ्यक्रम तैयार करने, प्रशिक्षण, तकनीकी प्रदर्शनियों और सम्मेलनों के आयोजन में भी सहयोग किया जाएगा।

यूपी के उद्योगों की 50 फीसद भागीदारी

इन सेंटरों में कम से कम 50 प्रतिशत भागीदारी उत्तर प्रदेश के उद्योगों की होगी, ताकि राज्य को इसका सीधा लाभ मिल सके। हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों और यूपीएसआरटीसी के माध्यम से कानपुर-लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर मार्ग पर ग्रीन हाइड्रोजन बसें चलाने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि यह पहल उत्तर प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक अहम केंद्र बनाएगी। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, निवेश आएगा और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

व्यापार जगत

टाटा मोटर्स फाइनेंस ने सेबी को चुकाए 32 लाख रुपए

टियर-टू परपेचुअल एनसीडी के पांच इश्यू से जुड़ा था विवाद

एजेंसी । नई दिल्ली

टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड ने बाजार नियामक सेबी के साथ चल रहे एक पुराने मामले को सुलझा लिया है। कंपनी ने नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (एनसीडी) जारी करने से जुड़े कथित नियम उल्लंघन के मामले में 32 लाख रुपए की सेटलमेंट राशि जमा की है। इसके बाद सेबी ने इस मामले को समाप्त कर दिया है। सेबी के मुताबिक, टाटा मोटर्स फाइनेंस ने खुद आगे बढ़कर मामले के निपटारे के लिए आवेदन किया था। कंपनी ने यह भी साफ किया कि वह आरोपों को न तो स्वीकार कर रही है और न ही खारिज कर रही है। सेबी ने तय शर्तों के तहत इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह विवाद नवंबर 2019 से जुलाई 2022 के बीच जारी किए गए टियर-टू परपेचुअल एनसीडी के पांच इश्यू से जुड़ा था। ये डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जारी किए गए थे। जांच में सामने आया कि छह महीने के भीतर ये एनसीडी 200 से अधिक निवेशकों को बेच दिए गए थे, जिनमें 460 करोड़ रुपए के गैर-सूचीबद्ध इश्यू भी शामिल थे।

शर्तों के उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

नियमों के अनुसार, यदि किसी सिक्योरिटी की पेशकश 200 से ज्यादा लोगों को की जाती है, तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं बल्कि पब्लिक इश्यू माना जाता है। सेबी का कहना था कि ऐसे में सार्वजनिक निर्गम से जुड़े नियमों का पालन जरूरी था, जो इस मामले में नहीं हुआ। 32 लाख रुपये की राशि जमा होने के बाद सेबी ने आदेश जारी कर कहा कि इस मामले में कंपनी के खिलाफ शुरू की जा सकने वाली सभी कार्रवाइयों का निपटारा कर दिया गया है। हालांकि, नियामक ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर भविष्य में दी गई जानकारी गलत पाई जाती है या शर्तों का उल्लंघन होता है, तो सेबी आगे की कार्रवाई कर सकता है।

KSH इंटरनेशनल का शेयर लिस्टिंग पर फिसला

निवेशकों को शुरुआती झटका, चार फीसद गिरावट के साथ हुआ सूचीबद्ध

एजेंसी । नई दिल्ली

मैग्नेट वाइंडिंग वायर बनाने वाली कंपनी केएसएच इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर की बाजार में शुरुआत कमजोर रही। मंगलवार को कंपनी का शेयर अपने निर्गम मूल्य 384 रुपए के मुकाबले करीब 4 फीसदी गिरावट के साथ सूचीबद्ध हुआ। लिस्टिंग के बाद कंपनी का कुल बाजार मूल्य करीब 2,437.85 करोड़ रुपए रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) दोनों पर केएसएच इंटरनेशनल का शेयर 370 रुपए पर सूचीबद्ध हुआ, जो इश्यू प्राइस से 3.64 फीसदी कम है। कारोबार शुरू होते ही शेयर में और गिरावट आई। बीएसई पर यह 7.55 फीसदी टूटकर 355 रुपए तक पहुंच गया, जबकि एनएसई पर शेयर 7.81 फीसदी गिरकर 354 रुपए पर आ गया। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए 365 से 384 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया था। पुणे स्थित केएसएच इंटरनेशनल का आईपीओ कुल 710 करोड़ रुपए का था, जिसमें 420 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए गए थे और 290 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल थी।

तीसरी बड़ी मैग्नेट वायर निर्माता कंपनी

केएसएच इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष 1979 में हुई थी। यह देश की तीसरी सबसे बड़ी मैग्नेट वायर निर्माता कंपनी है और निर्यात के मामले में सबसे आगे मानी जाती है। कंपनी 'केएसएच' ब्रांड के तहत पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों को उत्पाद सप्लाई करती है। इसके अलावा कंपनी अमेरिका, जर्मनी, यूएई और जापान सहित 24 देशों में निर्यात करती है। महाराष्ट्र के तलोजा और चाकन में कंपनी की तीन फैक्ट्रियां हैं, जबकि अहिल्यानगर के सुपा में नया प्लांट तैयार किया जा रहा है।

हाजिमे ओटा संभालेंगे जिम्मेदारी

नई दिल्ली। यामाहा मोटर इंडिया समूह को नया चेयरमैन मिल गया है। इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने हाजिमे ओटा को समूह का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वह एक जनवरी 2026 से अपना कार्यभार संभालेंगे। कंपनी के अनुसार, हाजिमे ओटा इससे पहले जापान स्थित यामाहा मोटर कंपनी लिमिटेड में कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं। इसके साथ ही वे कंपनी के वैश्विक मुख्यालय में कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी सेंटर के प्रमुख महाप्रबंधक (सीएसओ) भी रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कंपनी की रणनीति, सतत विकास और डिजिटल पहलों का नेतृत्व किया। अपनी नियुक्ति पर हाजिमे ओटा ने कहा कि भारत में यामाहा का नेतृत्व करना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि उनका मुख्य लक्ष्य ऐसे उत्पाद पेश करना होगा, जो यामाहा की वैश्विक तकनीक को भारतीय ग्राहकों की बदलती जरूरतों से जोड़ सकें।

2025: अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ी सफलता, निर्यात में बना रिकार्ड

नई दिल्ली। भारत ने इस साल अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। वाणिज्य मंत्रालय ने न्यूजीलैंड सहित तीन देशों के साथ महत्वपूर्ण व्यापार समझौते किए हैं। सोमवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत पूरी होने की घोषणा की गई। इससे पहले भारत ने जुलाई में ब्रिटेन के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) किया था। इसके बाद 18 दिसंबर को ओमान के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर हुए। इस तरह भारत ने एक ही साल में तीन बड़े व्यापार समझौते किए हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड के साथ हुआ एफटीए किसानों, डेयरी क्षेत्र और निर्यातकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने बताया कि यह समझौता केवल 9 महीनों में पूरा किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों की सातवीं बड़ी व्यापार डील है। खास बात यह है कि ये सभी समझौते विकसित देशों के साथ किए गए हैं।

बाजार में एंट्री के लिए तैयार कोल इंडिया की सहायक कंपनी

एजेंसी । मुंबई

नए साल 2026 की शुरुआत में शेयर बाजार में एक बड़ी सरकारी कंपनी की एंट्री हो सकती है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। झारखंड के धनबाद में मुख्यालय वाली इस कंपनी का आईपीओ अगले कुछ हफ्तों में आ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस आईपीओ में सिर्फ मौजूदा शेयरों की बिक्री होगी। कोल इंडिया अपनी करीब 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। इसके तहत लगभग 46.57 करोड़ शेयर बाजार में उतारे जाएंगे। कंपनी की ओर से कोई नए शेयर जारी नहीं होंगे, इसलिए आईपीओ से मिलने वाली पूरी राशि कोल इंडिया को जाएगी। आईपीओ का कुल आकार करीब 1,300 करोड़ रुपए हो सकता है। इसके आधार पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का मूल्यांकन लगभग 13,000 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। शेयर की कीमत, लॉट साइज और अन्य शर्तें आईपीओ के लॉन्च से पहले तय की जाएंगी। इस आईपीओ के बुक-रनिंग लीड मैनेजर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईडीबीआई कैपिटल होंगे, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज को रजिस्ट्रार बनाया गया है। सेबी ने सितंबर में ही कंपनी के ड्राफ्ट दस्तावेजों को मंजूरी दे दी थी। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड देश की बड़ी कोकिंग कोल उत्पादक कंपनियों में शामिल है। कोकिंग कोल स्टील बनाने में इस्तेमाल होता है। कंपनी नॉन-कोकिंग कोल और वॉशड कोल का भी उत्पादन करती है और स्टील व पावर सेक्टर को सप्लाई करती है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। कंपनी की खदानें झारखंड के झरिया और पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोलफील्ड्स में स्थित हैं।

नये साल पर आ सकता है बीसीसीएल का आईपीओ

2025 में हुआ 14000 करोड़ का कारोबार

पिछले कुछ वर्षों में कंपनी का उत्पादन लगातार बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022 में जहां उत्पादन 30 .51 मिलियन टन था, वहीं 2025 में यह बढ़कर 40 .50 मिलियन टन हो गया। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने करीब 14,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया और 1,240 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। कंपनी की नेटवर्थ भी बढ़कर 6,551 करोड़ रुपए हो गई है। खास बात यह है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड पूरी तरह कर्ज-मुक्त कंपनी है।

न्यूज़ ब्रीफ

हिंदू युवक की हत्या पर भारत में उबाल, दिल्ली-कोलकाता में प्रदर्शन

नई दिल्ली/कोलकाता। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस मॉब लिंचिंग के खिलाफ भारत में आक्रोश फैल गया है। मंगलवार को दिल्ली और कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद (VHP), बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किए। कहीं बांग्लादेशी हाई कमीशन के घेराव की कोशिश हुई, तो कहीं मोहम्मद यूनुस के पुतले फूंके गए। प्रदर्शन और पुलिस के बीच झड़पें भी देखने को मिलीं। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के पास स्थिति सबसे उग्र नजर आई। सैकड़ों प्रदर्शनकारी भगवा झंडे और बैनर लेकर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश में लगे। पुलिस ने तीन स्तर के बैरिकेड और 15 हजार पुलिस व अर्धसैनिक बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। प्रदर्शनकारियों को लगभग 800 मीटर पहले रोक दिया गया और DTC बसों को भी अवरोधक के रूप में लगाया गया। पोस्टरों पर नाराजगी जाहिर करने वाले नारे लिखे गए, जैसे "हिंदू रक्त की एक-एक बूंद का हिसाब चाहिए।" प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 18 दिसंबर को बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के बालुका इलाके में हुई घटना से उत्पन्न हुआ। 25 वर्षीय परिधान फैक्ट्री मजदूर दीपू चंद्र दास को कथित रूप से ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीटा, पेड़ से लटकाया और शव जला दिया।।

MP में SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 42.74 लाख नाम हटे

भोपाल। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है। इस बार की सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्यभर में कुल 42 लाख 74 हजार 160 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। राजधानी भोपाल में ही 4 .38 लाख से अधिक वोटरों के नाम कटे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और अद्यतन बनाने के लिए की गई है। SIR के तहत राज्य के 5 करोड़ 74 लाख 6 हजार 143 पंजीकृत मतदाताओं में से 5 करोड़ 31 लाख 31 हजार 983 मतदाताओं ने अपने गणना पत्रक (फॉर्म) जमा किए।

चक्रवात प्रभावित श्रीलंका को भारत की बड़ी मदद

45 करोड़ डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज

एजेंसी । कोलंबो

भारत ने चक्रवाती तूफान दित्वा से प्रभावित श्रीलंका के साथ एकजुटता दिखाते हुए 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता का ऐलान किया है। भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने मंगलवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सौंपा और संकट की घड़ी में भारत के समर्थन का भरोसा दिलाया। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह सहायता ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत की प्रथम रिस्पॉन्डर भूमिका को आगे बढ़ाते हुए दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अपने नेबरहुड फर्स्ट, विजन महासागर और सभ्यतागत संबंधों के आधार पर श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है।

पुनर्निर्माण पैकेज में क्या-क्या शामिल

भारत द्वारा घोषित 45 करोड़ डॉलर के पैकेज में कई अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें सड़क, रेलवे और पुल कनेक्टिविटी का पुनर्वास और बहाली पूरी तरह नष्ट और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों का निर्माण शामिल है। चक्रवात से प्रभावित स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को विशेष सहायता कृषि क्षेत्र में अल्पकालिक और मध्यम अवधि की कमी को दूर करने के उपाय बेहतर आपदा प्रतिक्रिया और तैयारी को मजबूत करना शामिल है।

किलिनोच्ची में बेली ब्रिज का उद्घाटन

इस दौरे के दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति और श्रीलंका के विदेश मंत्री के साथ मिलकर उत्तरी प्रांत के किलिनोच्ची जिले में स्थित 120 फुट लंबे दोहरी लेन वाले बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। यह इलाका चक्रवात दित्वा से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शामिल रहा है। डॉ. जयशंकर ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरासुरिया से भी मुलाकात की और चक्रवात के बाद श्रीलंका के पुनर्निर्माण में भारत की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत का यह पुनर्निर्माण पैकेज दोनों देशों के बीच गहरे और भरोसेमंद संबंधों का प्रतीक है।

नमो भारत ट्रेन में अश्लील हरकत का मामला, FIR दर्ज

गाजियाबाद। गाजियाबाद में संचालित नमो भारत ट्रेन से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। प्रीमियम कोच के भीतर युवक-युवती द्वारा कथित तौर पर अश्लील हरकत किए जाने और उसका वीडियो वायरल होने के बाद मुरादनगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच तेज कर दी है। एफआईआर के मुताबिक घटना 24 नवंबर 2025 की है। नमो भारत ट्रेन संख्या 23 दुहाई से मुरादनगर की ओर जा रही थी। आरोप है कि प्रीमियम कोच में यात्रा कर रहे एक युवक और एक युवती ने सार्वजनिक स्थान पर अशोभनीय कृत्य किया, जिससे सार्वजनिक शालीनता और गरिमा को ठेस पहुंची। मुरादनगर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 296 और 77 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।

हिंसाग्रस्त बलोचिस्तान

248 नागरिक और 205 सैनिक मारे गए

क्वेटा। आज़ादी की मांग और लगातार जारी विद्रोह के बीच पाकिस्तान का अशांत प्रांत बलोचिस्तान वर्ष 2025 में भी भीषण हिंसा की चपेट में रहा। हमलों, बम धमाकों और हथियारबंद घटनाओं में कम से कम 248 आम नागरिकों और 205 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। यह साल बलोचिस्तान के सबसे खूनी वर्षों में गिना जा रहा है।

द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट और सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2025 में बलोचिस्तान में कुल 432 हिंसक घटनाएं दर्ज की गईं। पूरे प्रांत में भय और असुरक्षा का माहौल बना रहा। लगातार हो रही हत्याओं और हमलों ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए।

आतंकवाद विरोधी अभियानों का दावा

बलोचिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि वर्षभर बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए गए। 2025 में पूरे प्रांत में 78,000 से अधिक खुफिया आधारित ऑपरेशन किए गए, जिनमें बलोच सशस्त्र समूहों के 707 सदस्यों के मारे जाने का दावा किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अभियान लगातार जारी हैं।

शांति की उम्मीदों पर पानी

अधिकारियों ने 2025 को बलोचिस्तान में शांति और स्थिरता के लिहाज से निराशाजनक साल बताया है। वहीं आलोचकों का आरोप है कि कई घटनाएं रिपोर्ट ही नहीं की जातीं और सुरक्षाकर्मियों के हताहतों की संख्या भी वास्तविकता से कम बताई जाती है।

लगातार जारी हिंसा, आत्मघाती हमले और जवाबी सैन्य अभियानों के बीच बलोचिस्तान में सुरक्षा हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक राजनीतिक समाधान और विश्वास बहाली के प्रयास नहीं होते, तब तक प्रांत में स्थायी शांति एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल क्वेटा, मस्तुंग, खुजदार, तुरबत और नोकुंडी में कुल छह आत्मघाती बम धमाके हुए।

अत्यधिक फास्ट फूड से 11वीं की छात्रा की मौत

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 11वीं कक्षा की छात्रा की मौत का कारण अत्यधिक फास्ट फूड का सेवन बताया गया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार, लंबे समय तक जंक फूड खाने से उसकी आंतें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थीं। छात्रा अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र के अफगान मोहल्ले की रहने वाली थी। परिजनों ने बताया कि उसे चाउमीन, मैगी, पिज़्ज़ा और बर्गर खाने की आदत थी। कुछ समय से उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, जिसके बाद पहले उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और गंभीर हालत में दिल्ली एम्स रेफर किया गया। एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि अत्यधिक फास्ट फूड के सेवन से छात्रा की आंतों में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। आंतों को साफ करने के लिए सर्जरी भी की गई, लेकिन इसके बावजूद छात्रा की जान नहीं बचाई जा सकी। प्रारंभिक तौर पर डॉक्टरों ने फास्ट फूड को ही उसकी मौत का मुख्य

पटना में नितिन नबीन का भव्य स्वागत

बोले— केरल से बंगाल तक लहराएगा भगवा

पटना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे नितिन नबीन का पटना में भव्य और शक्ति प्रदर्शन वाला स्वागत किया गया। छह किलोमीटर लंबे रोड शो और अभिनंदन समारोह के दौरान नितिन नबीन ने बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक भगवा लहराएगा।

6 किलोमीटर का रोड शो शक्ति प्रदर्शन

एयरपोर्ट से मिलर स्कूल ग्राउंड तक करीब 6 किलोमीटर का रोड शो निकाला गया। स्वागत के लिए हाथी, घोड़े और ऊंट की व्यवस्था की गई थी। जगह-जगह समर्थक फूल बरसाते दिखे, जबकि बड़ी संख्या में महिलाएं भी रोड शो में शामिल रहीं। मिलर स्कूल ग्राउंड पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'जय श्री राम' के नारे लगाए।

राहुल गांधी पर तीखा हमला

नितिन नबीन ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की जनता राहुल गांधी को सजा देगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "बिहार की जनता ने राहुल गांधी को इस तरह भगाया कि वह जर्मनी चले गए। यह पार्ट टाइम राजनीति है। चुनाव हारते हैं तो विदेश घूमने चले जाते हैं।"

इस दौरान नितिन नबीन ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला और कहा कि जनता ऐसे लोगों को समय आने पर जवाब देगी। उन्होंने कहा कि अब राजनीति में स्पष्ट सोच और जमीन से जुड़े नेतृत्व का वक्त है।

'पंचायत से पार्लियामेंट तक परचम'

नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य पंचायत से पार्लियामेंट तक परचम लहराना है। इसके लिए पंचायत चुनाव से ही कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ जुटने की जरूरत है। उन्होंने बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। अभिनंदन समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे।

विकसित बिहार की दिशा में सरकार का फोकस

पटना। बिहार को विकसित राज्य बनाने के अभियान को तेज करते हुए राज्य सरकार ने सात निश्चय-3 की जानकारी हर घर तक पहुंचाने का फैसला किया है। जनसंपर्क विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की गलत सूचना और अफवाह का तुरंत खंडन किया जाना चाहिए।

मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जनसंपर्क विभाग सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो और डिजिटल माध्यमों के जरिए जनता तक पहुंचा रहा है। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम, आउटडोर होर्डिंग्स, फ्लेक्स, चैटबॉट और इन्फ्लूएंसर्स का भी उपयोग किया जा रहा है। सात निश्चय-3 को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विभाग 15 प्रमुख थीम्स पर काम करेगा।

सीएम मोहन यादव का बैतूल में बड़ा ऐलान

बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक बन गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिले में बनने वाले नए मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन किया। इसी मौके पर मुख्यमंत्री ने ताप्ती उद्गम स्थल मुलताई शहर का नाम बदलकर 'मुलतापी' करने की बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सूर्यपुत्री मां ताप्ती की महिमा को रेखांकित करते हुए कहा कि जिलेवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि मुलताई अब 'मुलतापी' के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजेगी।

बैतूल के पुलिस ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में जिले के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉलेज क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।

जुबैर रहमान बने बांग्लादेश के चीफ जस्टिस

एजेंसी । ढाका

बांग्लादेश में सियासी हलचल के बीच नया मोड़ आया है। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी जुबैर रहमान चौधरी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगाई है। जुबैर 27 दिसंबर से अपना पदभार संभालेंगे।

डेली ऑब्जर्वर के अनुसार, 22 दिसंबर को बंगभवन में बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्तमान चीफ जस्टिस सैयद रिफात अहमद के रिटायर होने के बाद जुबैर रहमान चौधरी को उनका स्थान दिया जाएगा। चौधरी इससे पहले अपीलीय न्यायालय प्रभाग के न्यायाधीश थे।

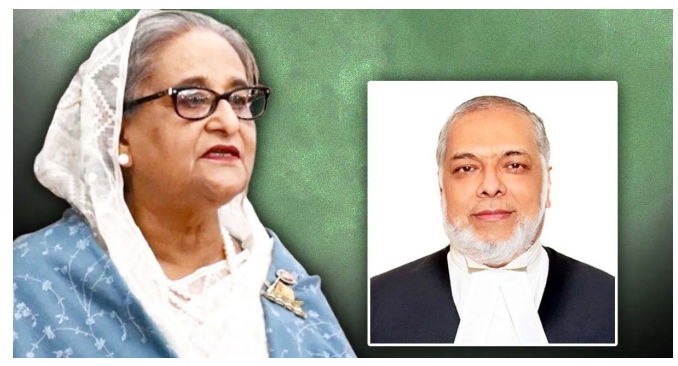

शेख हसीना के करीबी जुबैर

जुबैर रहमान को शेख हसीना का करीबी माना जाता है। शेख हसीना के कार्यकाल में उनका कद बढ़ा। वे मशहूर न्यायाधीश एएनएम रहमान चौधरी के बेटे हैं। 2007 में जुबैर ने शेख हसीना को एक्सटॉर्शन मामले में राहत दी थी, जिसके बाद उनका राजनीतिक उत्थान हुआ। 2008 में शेख हसीना प्रधानमंत्री बनीं और जुबैर ढाका हाईकोर्ट पहुंचे। उनके कोर्ट में कई मामले आए जिनमें शेख हसीना को राहत मिली, जबकि अन्य मामलों में उन्हें सख्त सजा दी गई। जुबैर की नियुक्ति ऐसे वक्त में हुई है जब बांग्लादेश में चुनाव प्रक्रिया तेज है। आवामी लीग और अंतरिम सरकार के बीच चुनाव में शामिल करने को लेकर तनातनी बढ़ रही है।

खलीलुर रहमान के होम एडवाइजर बनने की चर्चा

जुबैर के चीफ जस्टिस बनने के बाद अब खलीलुर रहमान को होम एडवाइजर बनाए जाने की चर्चा चल रही है। खलीलुर बांग्लादेश सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और पिछले महीनों में आवामी लीग की वापसी को लेकर विदेश में चर्चा कर चुके हैं। वर्तमान स्थिति में उनकी भूमिका को अहम माना जा रहा है। इस नियुक्ति और आगामी प्रशासनिक फेरबदल से बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

पुलिस वैन पर हमला पांच कांस्टेबल शहीद

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले में सोमवार को पुलिस वैन पर हुए घातक हमले में पांच पुलिस कांस्टेबलों की मौत हो गई। यह हमला करक के गुरगुरी इलाके में उस समय हुआ, जब पुलिसकर्मी नियमित गश्त पर थे।

जिला पुलिस अधीक्षक शौकत खान ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हमले में पांचों कांस्टेबल मौके पर ही शहीद हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके

को घेर लिया गया है और हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

शहीद कांस्टेबलों की पहचान

डान अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, शहीद पुलिसकर्मियों की पहचान कांस्टेबल शाहिद इकबाल, समीउल्लाह, आरिफ, सफदर और मोहम्मद अबरार के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी कांस्टेबल रोज की तरह गश्त पर निकले थे, तभी हमलावरों ने घात लगाकर उनकी वैन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं।

दुनिया न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में अब तक खैबर पख्तूनख्वा में हुए आतंकी हमलों में सुरक्षा बलों समेत 502 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान प्रांत में 1,588 आतंकी घटनाएं दर्ज की गईं।

नागरिकों और पुलिस को भारी नुकसान

खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, इन हमलों में 223 नागरिक मारे गए और 570 घायल हुए। वहीं 137 पुलिस अधिकारी शहीद हुए और 236 घायल हुए। इसके अलावा विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 18 कर्मियों ने भी अपनी जान गंवाई।

रिपोर्ट में बताया गया है कि आतंकी हमलों में फेडरल कांस्टेबुलरी के 124 कर्मी शहीद हुए और 244 घायल हुए। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने कई अभियानों को अंजाम दिया, जिनमें 348 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया गया है।

बन्नू सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र

आंकड़ों के अनुसार, आतंकवाद से जुड़ी सबसे अधिक 394 घटनाएं बन्नू क्षेत्र में दर्ज की गईं। यहां 41 पुलिस अधिकारी शहीद हुए और 89 घायल हुए। इसके साथ ही 54 नागरिकों की मौत और 125 के घायल होने की सूचना है। डेरा इस्माइल खान, उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तान जैसे इलाकों में भी हिंसा की घटनाएं सामने आईं। उत्तरी वजीरिस्तान में 181 मामलों में 38 नागरिकों की मौत और 182 लोग घायल हुए। दक्षिणी वजीरिस्तान में 103 मामलों में 39 नागरिक मारे गए और 86 घायल हुए। लगातार बढ़ती हिंसा ने खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा हालात को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है।

बर्लिन में राहुल गांधी का 'वोट चोरी' आरोप

BJP ने किया पलटवार

एजेंसी । नई दिल्ली

जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है। हर्टी स्कूल में छात्रों से बातचीत के दौरान राहुल ने BJP पर संविधान को खत्म करने और चुनावी प्रक्रिया से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। उनके इस बयान पर BJP ने इसे विदेश में भारत की छवि खराब करने वाला करार देते हुए तीखा पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस जीत चुकी थी, लेकिन नतीजे बदले गए। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनावों को भी निष्पक्ष न ठहराने का आरोप लगाया। राहुल ने दावा किया कि देश के लाखों लोग सरकार और RSS से अलग सोचते हैं, लेकिन उनकी आवाज दबाई जा रही है। कांग्रेस ने इस बातचीत का लगभग एक घंटे लंबा वीडियो जारी किया, जिसमें राहुल ने वही आरोप दोहराए जो देश में भी उठाते रहे हैं।

'दुनिया के 29 देशों ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया'

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल के बयानों को देश का अपमान करार दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के 29 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया, जबकि राहुल विदेश जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि RSS को समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने पड़ेंगे।

केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने राहुल को 'बच्चा' बताते हुए कहा कि संसद सत्र के दौरान विदेश जाकर देश के खिलाफ बयान देना गैरजिम्मेदाराना है। BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल की तुलना मीर जाफर से की और उन पर देश विरोधी ताकतों से संबंध रखने का आरोप लगाया।

सोरोस कनेक्शन का आरोप

BJP ने दावा किया कि हर्टी स्कूल की प्रोफेसर कॉर्नेलिया वोल का संबंध अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस से है। पार्टी का आरोप है कि सोरोस भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस उनसे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी ने भी इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी। सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि देश के बाहर भारत के खिलाफ बयानबाजी से सभी दलों को बचना चाहिए और राजनीतिक मुद्दों को विदेश में नहीं ले जाना चाहिए। इस पूरे विवाद ने राजनीतिक बहस को गर्मा दिया है और आगामी चुनावी माहौल में इसका असर देखा जा सकता है।

कोने-कोने से...

जालना मनपा चुनाव: पहले ही दिन 804 नामांकन पत्र बिके, दाखिल एक भी नहीं

जालना। जालना शहर में आगामी जालना महानगरपालिका सार्वत्रिक चुनाव 2025 की प्रक्रिया ने औपचारिक रूप से गति पकड़ ली है। मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 से नामांकन पत्रों की बिक्री और स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू होते ही चुनावी माहौल स्पष्ट रूप से सक्रिय नजर आने लगा है। पहले ही दिन उम्मीदवारों की भारी दिलचस्पी देखने को मिली, हालांकि नामांकन दाखिल करने के मामले में अभी प्रतीक्षा बनी हुई है। प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पहले से ही पूरी तरह तैयार है। शहर के 15 विभागों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है, जबकि पांच निर्वाचन निर्णय अधिकारियों के कार्यालयों में नामांकन से जुड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच इन सभी कार्यालयों में इच्छुक उम्मीदवारों की उल्लेखनीय भीड़ देखी गई। नामांकन प्रक्रिया के पहले ही दिन कुल 804 नामांकन पत्रों की बिक्री दर्ज की गई, जो चुनाव को

15 चुनाव निर्णय अधिकारियों की नियुक्ति

पुणे। पुणे महानगरपालिका के आगामी आम चुनाव 2025-26 के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 15 चुनाव निर्णय अधिकारियों (आरओ) की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही प्रत्येक अधिकारी की सहायता के लिए सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी (1, 2 और 3) भी नियुक्त किए गए हैं और सभी कार्यालयों के स्थान निश्चित कर दिए गए हैं। चुनाव संबंधी कामकाज के लिए कुल 22 विशेष कक्ष स्थापित किए गए हैं, जिनके लिए 15 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा, चुनाव निर्णय अधिकारियों के स्तर पर भी 22 कक्षों के लिए अलग से नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए पुणे मनपा ने 'अनापत्ति बकाया प्रमाण पत्र' (एनओसी) प्राप्त करने हेतु एक विशेष कंप्यूटर प्रणाली उपलब्ध कराई है।

यशोमति ठाकुर बनीं कांग्रेस की स्टार प्रचारक

अमरावती। आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें अमरावती से संबंध रखने वाली कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री यशोमति ठाकुर का नाम भी शामिल है। इस सूची में प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार, सांसद मुकुल वासनिक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सचिन पायलट, अभिनेता राज बब्बर, जिग्नेश मेवाणी, कन्हैया कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। यशोमति ठाकुर अमरावती मनपा के चुनाव पर विशेष ध्यान देंगी और राज्य के सभी मनपा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार करेंगी, जबकि पार्टी ने राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं।

जेन जी

मैं अपने वोट का इस्तेमाल उस पार्टी के लिए करना चाहता हूँ जो शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दे। मुझे लगता है कि केवल वादों से काम नहीं चलेगा, हमें नेताओं के पिछले काम और उनकी छवि को देखकर निर्णय लेना चाहिए।

– आयुष जैसवार, मुंबई

युवा वर्ग सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से काफी प्रभावित है। मैं ऐसे नेताओं को पसंद करती हूँ जो पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। मेरे लिए यह जरूरी है कि वे जनता की समस्याओं को समझें और उनका समाधान करें।

– यश यादव, मुंबई

हमें भेजें

अगर आप भी अपने विचार हमें भेजना चाहते हैं तो 8356804318 इस नंबर पर व्हाट्सप्प करें।

विश्लेषण

बीएमसी चुनाव

मुस्लिम वोट बैंक पर है सबकी नजर

अमित बृज । मुंबई

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस बार का चुनाव कई मायनों में अब तक का सबसे अलग और दिलचस्प माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे अपनी सियासी विरासत और मुंबई पर पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्षरत हैं, वहीं भाजपा एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर बीएमसी पर कब्जा जमाने की रणनीति में जुटी है। इस बार गठबंधन और बिखराव दोनों ही चुनावी गणित को जटिल बना रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि महायुति के प्रमुख घटक उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। दूसरी ओर, कांग्रेस ने भी महाविकास अघाड़ी से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। इन फैसलों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दोनों दल मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने के लिए जानबूझकर गठबंधन से दूरी बना रहे हैं।

वार्ड-वाइज मुस्लिम प्रभाव (संक्षिप्त विश्लेषण)

दक्षिण मुंबई (मुंबादेवी, भेंडी बाजार, मझगांव बेल्ट)

- यहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। कांग्रेस, सपा और AIMIM की सीधी टक्कर मानी जा रही है।

मध्य मुंबई (कुर्ला, चेंबूर, सायन–धारावी क्षेत्र)

- उत्तर भारतीय मुस्लिम आबादी ज्यादा है। यहां अजित पवार की एनसीपी और सपा की पकड़ मजबूत मानी जाती है, जबकि शिवसेना भी मराठी मुस्लिम वोट पर नजर रखे है।

पश्चिमी उपनगर (जोगेश्वरी, गोरेगांव, अंधेरी ईस्ट–वेस्ट)

- मिश्रित आबादी के चलते मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव–शिंदे दोनों गुट) और बीजेपी की सीधी टक्कर संभव है।

पूर्वी उपनगर (मानखुर्द, गोवंडी)

- मुस्लिम वोट यहां सबसे ज्यादा संगठित है। AIMIM, सपा और कांग्रेस के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा मानी जा रही है।

मुंबई में मुस्लिम वोट : चुनाव की मास्टर-की

महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी भले ही करीब 12 फीसदी हो, लेकिन मुंबई में यह आंकड़ा 20 फीसदी से अधिक है। बीएमसी की 277 सीटों में से लगभग 45 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जबकि करीब 30 वार्ड ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन के बिना जीत संभव नहीं मानी जाती। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी हुई है।

मुस्लिम वोटों का बिखराव, किसे मिलेगा फायदा?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि विपक्षी दल मुस्लिम वोटों को एकजुट करने में नाकाम रहे, तो इसका सीधा फायदा भाजपा-शिंदे शिवसेना गठबंधन को मिल सकता है। जिस तरह से कांग्रेस, एनसीपी (दोनों गुट), सपा और AIMIM अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उससे मुस्लिम वोटों का विभाजन लगभग तय है।

47 वार्डों में मुस्लिम वोटरों की संख्या अधिक

2017 मुस्लिम पार्षद

- कांग्रेस: 11
- समाजवादी पार्टी: 6
- एनसीपी: 4
- AIMIM: 3
- शिवसेना: 2
- निर्दलीय: 5

मुस्लिम समाज

- करीब 70% मुस्लिम उत्तर भारतीय मूल के हैं
- लगभग 30% मराठी, गुजराती, दक्षिण भारतीय और अन्य समुदायों से आते हैं

2017 के आंकड़े बताते हैं मुस्लिम वोट की ताकत

2017 के बीएमसी चुनाव में कुल 31 मुस्लिम पार्षद चुने गए थे। इनमें 11 कांग्रेस से, 6 समाजवादी पार्टी से, 4 एनसीपी से, 3 AIMIM से, 2 शिवसेना से और 5 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल थे। ये आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि मुस्लिम वोट किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रणनीति और समीकरण के अनुसार बंटता रहा है।

मराठी बनाम गैर-मराठी मुस्लिम समीकरण

मुंबई के मुस्लिम समाज के भीतर भी आंतरिक विभाजन है। करीब 70 फीसदी मुस्लिम उत्तर भारतीय पृष्ठभूमि से हैं, जबकि 30 फीसदी में मराठी, गुजराती, दक्षिण भारतीय और अन्य समुदाय शामिल हैं। मराठी मुस्लिमों का एक वर्ग परंपरागत रूप से शिवसेना के साथ रहा है, जबकि गैर-मराठी मुस्लिम वोट कांग्रेस, एनसीपी और सपा में बंटता रहा है। यह सामाजिक संरचना चुनावी रणनीतियों को और जटिल बनाती है।

कितने दावेदार, कितना बिखराव?

बीएमसी चुनाव की घोषणा के साथ ही मुस्लिम वोटों को साधने की होड़ तेज हो गई है। कांग्रेस, अजित पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी (एसपी), समाजवादी पार्टी, AIMIM के साथ-साथ उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेल रही हैं। इतने अधिक दावेदारों के बीच मुस्लिम वोटों का बिखराव तय माना जा रहा है।

कांग्रेस की रणनीति : मुस्लिम वोटों पर सीधा दांव

कांग्रेस जानती है कि बिना मुस्लिम समर्थन के बीएमसी में उसकी वापसी मुश्किल है। यही वजह है कि उद्धव-राज ठाकरे के संभावित गठबंधन के बीच कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया, ताकि मुस्लिम वोट एकमुश्त उसके खाते में आएं। कांग्रेस की कोशिश है कि वह मुस्लिम मतदाताओं की 'पहली पसंद' बनी रहे।

अजित पवार का दांव : नवाब मलिक और उत्तर भारतीय मुस्लिम

अजित पवार ने बीएमसी चुनाव प्रबंधन की कमान नवाब मलिक को सौंपकर कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति बनाई है। उनकी चुनावी समिति में उत्तर भारतीय मुस्लिम चेहरों को प्रमुखता दी गई है, जिनमें नवाब मलिक और जीशान सिद्दीकी जैसे नाम शामिल हैं। भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना की नवाब मलिक को लेकर असहजता भी अजित पवार के अकेले चुनाव लड़ने की बड़ी वजह मानी जा रही है।

AIMIM और सपा की चुनौती

कुछ समय पहले तक मुस्लिम वोटों के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही AIMIM इस बार कमजोर स्थिति में दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी विधानसभा चुनावों में गठबंधन को लेकर मिले झटकों के बाद अकेले मैदान में है। इन दोनों दलों की मौजूदगी मुस्लिम वोटों के और अधिक बंटवारे का कारण बन सकती है।

मुस्लिम वोट इस चुनाव की धुरी

बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निगम की सत्ता का चुनाव नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करने वाला मुकाबला है। मुस्लिम वोट इस चुनाव की धुरी बन चुका है। सवाल यही है—क्या मुस्लिम मतदाता किसी एक दल के पीछे एकजुट होंगे या फिर बिखराव का फायदा सत्तारूढ़ गठबंधन उठाएगा? इसका जवाब बीएमसी के नतीजे ही देंगे।

DBD इन्फो

मुंबई महानगरपालिका वॉर्ड सिस्टम की पूरी एबीसी

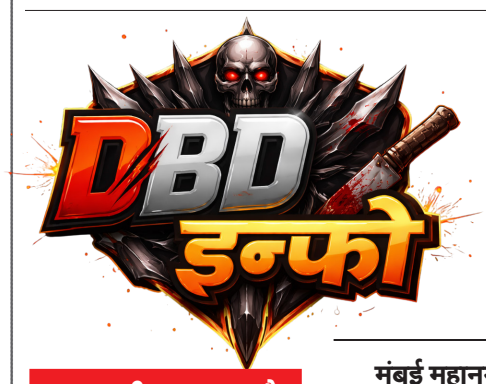

धीरज सिंह । मुंबई

मुंबई महानगरपालिका यानी BMC चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। BMC भारत की सबसे बड़ी नगरपालिका है और इसका काम शहर की साफ-सफाई, पानी, सड़कों, कचरा प्रबंधन, लाइसेंस, अस्पताल, स्कूल और नागरिक सेवाओं का संचालन करना होता है। इसके लिए शहर को अलग-अलग हिस्सों में बाँटा गया है जिन्हें 'वॉर्ड' कहा जाता है।

BMC की स्थापना और वॉर्ड्स का पहला स्वरूप

BMC की स्थापना साल 1873 में हुई थी। शुरुआत में यह सिर्फ दक्षिण मुंबई तक ही सीमित थी। उस समय मुंबई एक छोटा-सा इलाका था और बहुत सीमित जनता इसके अंतर्गत आती थी। जैसे-जैसे शहर का विस्तार हुआ, BMC की सीमाएं भी बढ़ती गईं। 1950 के दशक में मुंबई के उपनगरों को भी BMC के अंतर्गत लाया गया।

प्रशासनिक वॉर्ड्स क्या होते हैं?

मुंबई को प्रशासनिक रूप से 24 वॉर्ड्स में बांटा गया है। इन्हें अंग्रेजी अक्षरों के नाम A से T तक दिया गया है। हर वॉर्ड में BMC का एक ऑफिस होता है जिसे ३वॉर्ड ऑफिसर३ कहा जाता है। वहां एक सहायक आयुक्त होता है जो इलाके में पानी, सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य नागरिक सुविधाओं की निगरानी करता है।

आरक्षण की व्यवस्था

BMC वॉर्ड्स में आरक्षण की व्यवस्था होती है। कुल सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदायों के लिए भी आरक्षण तय होता है। हर चुनाव से पहले यह आरक्षण घुमाव पद्धति से तय किया जाता है।

निर्वाचन वॉर्ड्स और उनकी संख्या

प्रशासनिक वॉर्ड को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटकर 'निर्वाचन वॉर्ड' बनाए जाते हैं, जिनसे नगरसेवक चुने जाते हैं। शुरुआत में इनकी संख्या 170 थी। 1991 की जनगणना के बाद इसे बढ़ाकर 221 किया गया और 2002 में 227 कर दिया गया। वर्तमान में मुंबई में 227 निर्वाचन वॉर्ड्स हैं।

वॉर्ड्स में बदलाव

साल 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने BMC के वॉर्ड्स की संख्या बढ़ाकर 236 कर दी थी, ताकि बढ़ती आबादी को बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सके। पूर्व और पश्चिम उपनगरों में नए वॉर्ड जोड़े गए। लेकिन बाद में सरकार ने इसे वापस 227 कर दिया।

कोर्ट का फैसला

इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए 236 वॉर्ड्स के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अब इस साल होने वाले मुंबई महानगरपालिका चुनाव 227 निर्वाचन वॉर्ड्स के हिसाब से ही होंगे।

वॉर्ड्स का निर्धारण और डिलिमिटेशन

हर दस साल में जनगणना के बाद वॉर्ड्स का पुनर्विभाजन यानी 'डिलिमिटेशन' किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि हर वॉर्ड में लगभग समान जनसंख्या हो। BMC में हर निर्वाचन वॉर्ड की औसतन आबादी लगभग 55,000 होती है। डिलिमिटेशन में इलाके की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक संरचना और सुविधाओं को ध्यान में रखकर सीमाएं तय की जाती हैं।

मुंबई के 24 प्रशासनिक वॉर्ड्स और उनके क्षेत्र

मुंबई को 24 प्रशासनिक वॉर्ड्स में बांटा गया है। उदाहरण के लिए, A वॉर्ड में कोलाबा और फोर्ट, B वॉर्ड में मांडवी और मस्जिद बंदर, C वॉर्ड में मरीन लाइन्स और चंदनवाडी, D वॉर्ड में गिरगांव और ग्रांट रोड, E वॉर्ड में भायखळा और नागपाडा, F वॉर्ड में माटुंगा, सायन, परेल और शिवड़ी, G वॉर्ड में दादर, वरळी, महिम, प्रभादेवी, H वॉर्ड में सांताक्रूज, खार, K वॉर्ड में अंधेरी, वर्सोवा, L वॉर्ड में कुर्ला और चेंबूर, M वॉर्ड में गोवंडी और टिळक नगर, N वॉर्ड में घाटकोपर, P वॉर्ड में मलाड और गोरेगांव, R वॉर्ड में बोरिवली और कांदिवली, S वॉर्ड में भांडुप और T वॉर्ड में विक्रोली आते हैं।

वॉर्ड वॉर – मुंबई मनपा चुनाव

जी उत्तर वार्ड

त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद

मुंबई के धारावी, सायन, माहिम और दादर इलाके बीएमसी के जी उत्तर वार्ड में आते हैं। इस वार्ड में करीब 6 लाख की आबादी है और यहां 11 नगरसेवक सीटें हैं। पिछले तीन वर्षों तक चुनाव न होने के कारण स्थानीय लोगों के पास जन-प्रतिनिधि नहीं थे, जिससे शिकायतों का त्वरित समाधान नहीं हो पाया। इस वार्ड में नगरसेवक की 11 सीटें हैं, जहां पिछले चुनाव में शिवसेना का दबदबा देखने को मिला था। इस वर्ष शिवसेना (उद्धव गुट), कांग्रेस और भाजपा में त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद लगाई जा रही है।

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)

इलाके की समस्याएं

जी उत्तर वार्ड में स्थानीय निवासी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें शिवाजी पार्क में प्रदूषण, माहिम कॉजवे पर लगातार ट्रैफिक जाम, पानी के कनेक्शन न मिलना और बीएमसी की अधूरी परियोजनाएं प्रमुख हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है और लोग नए नगरसेवकों से इन मुद्दों के समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

वार्ड-वाइज चुनावी रिपोर्ट

वार्ड 182 – मिलिंद वैद्य (शिवसेना, ओबीसी)

- इस वार्ड में शिवसेना के मिलिंद वैद्य ने 6,899 वोटों के साथ जीत हासिल की। ओबीसी आरक्षण वाले इस वार्ड में उनकी लोकप्रियता लगातार बनी हुई थी।

वार्ड 183 – गंगा माने (कांग्रेस, अनुसूचित जाति महिला)

- गंगा माने ने इस वार्ड में कांग्रेस के पक्ष में 3,896 वोट हासिल किए। महिला आरक्षण होने के बावजूद कांग्रेस को यहां अपेक्षाकृत कम वोट मिले।

वार्ड 184 – बब्बू खान (कांग्रेस, महिला)

- बब्बू खान ने 7,017 वोटों के साथ वार्ड 184 में जीत दर्ज की। यह वार्ड महिला आरक्षण के तहत आता है और कांग्रेस की पकड़ मजबूत रही।

वार्ड 185 – थैवलपिल मक्कुनी (शिवसेना, सामान्य)

- थैवलपिल मक्कुनी ने 5,802 वोटों के साथ इस सामान्य श्रेणी वाले वार्ड में जीत हासिल की। शिवसेना का प्रभाव यहां पिछले चुनावों से कायम है।

वार्ड 186 – वसंत नकाशे (शिवसेना, अनुसूचित जाति महिला)

- अनुसूचित जाति महिला आरक्षण वाले इस वार्ड में वसंत नकाशे ने 8,794 वोट लेकर जीत दर्ज की। यह शिवसेना के लिए मजबूत क्षेत्र माना जाता है।

वार्ड 187 – मरिअम्माल वेवर (शिवसेना, ओबीसी)

- मरिअम्माल वेवर ने 6,876 वोट प्राप्त किए और वार्ड 187 में जीत सुनिश्चित की। ओबीसी आरक्षण वाले इस वार्ड में विसेना की पकड़ मजबूत रही।

वार्ड 188 – रेशमा बानो खान (राकांपा, सामान्य)

- इस सामान्य श्रेणी वाले वार्ड में राकांपा की रेशमा बानो खान ने 7,150 वोट लेकर जीत हासिल की। राकांपा का यह क्षेत्रीय प्रभुत्व दर्शाता है।